

शर्यहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-28 अंक-16

22 अगस्त से 5 सितम्बर, 2013

मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती

मूल्य : 2 रुपये

देश भर में सम्मानपूर्वक मनाया गया कॉमरेड शिवदास घोष का 37वां स्मृति दिवस



दिल्ली में स्मृति सभा को संबोधित करते हुए कॉ. के. राधाकृष्ण (इनसेट में)

5 अगस्त का दिन अपने दिवंगत नेता एसयूसीआई (सी) के संस्थापक महासचिव, इस युग के महान् मार्क्सवादी चिन्तनकार कॉमरेड शिवदास घोष को श्रद्धांजली देने और उनके सपनों को साकार बनाने की शपथ लेने का दिन है। उनके 37वें स्मृति दिवस पर देश भर में स्मृति सभाएं की गईं। हर जगह कार्यक्रम की शुरुआत कॉमरेड शिवदास घोष की तस्वीर पर माल्यार्पण व उन पर रचित गीत से हुई व समापन अंतर्राष्ट्रीय गान से हुआ। दिल्ली

इस अवसर पर यहां गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के सभागार में 8 अगस्त को सभा की गई। सभा की अध्यक्षता पार्टी के दिल्ली राज्य सांगठनिक कमिटी के वरिष्ठ सदस्य डॉ. प्राण शर्मा ने की। एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) की केन्द्रीय कमिटी के सदस्य और कर्नाटक राज्य कमिटी के सचिव डॉ. के. राधाकृष्ण सभा के मुख्य वक्ता थे। पार्टी के दिल्ली राज्य सचिव डॉ. प्रताप सामल ने भी सभा को संबोधित किया।

पंजाब

बुढ़लाडा : सर्वहारा के महान नेता, इस युग के महान मार्क्सवादी दार्शनिक व चिंतक तथा हमारी पार्टी एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के संस्थापक महासचिव, नेता, शिक्षक व पथ प्रदर्शक कॉमरेड शिवदास घोष के 37 वें स्मृति दिवस के अवसर पर 10 अगस्त को बुढ़लाडा के एफसीआई हॉल में स्मृति सभा हुई। सभा के मुख्य वक्ता थे पार्टी के केन्द्रीय कमिटी सदस्य और हरियाणा राज्य सचिव डॉ. सत्यवान। उन्होंने कहा कि पूँजीवाद ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। इन दमघोंटू हालात के खिलाफ दुनिया भर में लोग आवाज उठाते हुए सड़कों पर उतरे हुए हैं। पूँजीपति शासकों का सिंहासन हिल रहा है। यहाँ इन स्वतःस्फूर्त आन्दोलनों को क्रान्तिकारी दिशा देने में क्रान्तिकारी पार्टी की भूमिका है। उन्होंने देश में एकमात्र सही कम्युनिस्ट पार्टी एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) को मजबूत करने की अपील की। सभा की अध्यक्षता (शेष पृष्ठ 2 पर)

कांग्रेस - नीत यूपीए सरकार द्वारा यह कहने की धृष्टता करने कि शहीद - ए - आजम भगत सिंह कोई शहीद नहीं थे की एसयूसीआई (सी) ने की कड़ी निन्दा

एसयूसीआई (सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 17 अगस्त को जारी एक बयान में कहा :

हमारे देश के आजादी आन्दोलन के उफान भरे दिनों से जहाँ पूरे देश और पूरी दुनिया के आजादी-पसंद लोग शहीद - ए - आजम भगत सिंह के आगे श्रद्धा से शीश नवाते आये हैं, जिन्होंने अपनी शूरवीरता और सच्चे हृदय से व जोशीली देशभक्ति से पूरे राष्ट्र के समूचे ताने-बाने को झकझोर कर रख दिया था, जिनके अत्यंत महत्वपूर्ण शहादत को हसते-हसते गले लगाने ने मातृभूमि को विदेशी हुकूमत के जुए से आजाद कराने के संघर्ष को नई बुलन्दियों पर पहुंचाते हुए नवजीवन दिया था और जो हर तरह के दमन और अन्याय के खिलाफ अपना न्यायोचित संघर्ष चलाने में आज भी लोगों को प्रेरित करता जा रहा है, उस शहीद - ए - आजम भगत सिंह के बारे में कांग्रेस - नीत सरकार द्वारा यह कहना कि वे शहीद नहीं थे, न केवल बहुत ही धृष्ट बल्कि अक्षम्य कृत्य है। लाखों लाख देशवासियों के लिए, यह दुष्टतापूर्ण बयान बेमायने और नितांत महत्वहीन है इसलिए रहीं की तरह कूड़ेदान में फेंकने लायक है।

संवेहातीत रूप से यह एक बार फिर दर्शा देता है कि भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता की समझौतापरस्त धारा का प्रतिनिधित्व करने वाला शासक भारतीय राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग भारतीय राष्ट्रीय आजादी आन्दोलन की गौर समझौतावादी धारा के बहादुर योद्धाओं से कितना भयभीत है और उनके प्रति कितना तिरस्कारपूर्ण है और भगत सिंह जैसे विरले किस्म के ज्वलंत गौरसमझौतावादी लड़ाकू चरित्र की शानदार विरासत को मलियामेट कर देने पर तृप्ता हुआ है बल्कि हमारे ऐतिहासिक आजादी आन्दोलन के इतिहास को तोड़मरोड़ कर पेश करने की भी चोरी छिपे कोशिश कर रहा है ताकि देश के लोग, खास कर युवा इससे अनभिज्ञ रहें कि शहीद - ए - आजम भगत सिंह व उन जैसे अन्य चर्चित व्यक्तित्वों के अग्नि युग का देश के देशभक्त लोगों पर कितना जबरदस्त असर पड़ा था। उनके एहसानमंद देशवासी बुर्जुआ शासकों के इस अत्यंत भर्त्सनायोग्य और निहायत गन्दे बयान की कड़ी निन्दा करते हैं और यौवन से भरपूर आज, अदम्य जज्बे और अमिट देशभक्ति के साकार रूप में अमर हो गये उन महान राष्ट्रीय नायकों के प्रति जिन्होंने ऐसा हेय ठहराने वाला रवेया दिखाया है उन्हें उदाहरणमूलक कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। अतः, हम देश के लोगों से कांग्रेस और उन सब अन्य बुर्जुआ पार्टियों को ऐसे अविवेक के खिलाफ बगावत में उठ खड़े होने का आह्वान करते हैं जो इतनी निर्लज्जता से महान राष्ट्रीय नायकों को बदनाम करने वाला इसी तरह का धृष्ट रवेया और नजरिया रखती हैं।

विनाशकारी है आंध्र प्रदेश के बंटवारे का फैसला

एस.यू.सी.आई. (सी) की केन्द्रीय कमिटी की ओर से महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 1 अगस्त को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि आंध्र प्रदेश को दो भागों में बांटने के केन्द्र सरकार के फैसले का हम जोरदार विरोध करते हैं।

1950 में हुए एक विशाल आन्दोलन के जरिये जो आंध्र प्रदेश राज्य बना था उसे बिना किसी स्वीकार्य तर्क के कांग्रेस-नीत यूपीए की केन्द्र सरकार ने दो भागों में बांटने का जो एकतरफा फैसला लिया है वह सिर्फ इतना ही नहीं कि आंध्र प्रदेश की जनता के बीच फूट डालेगा, बल्कि पूरे देश के लिए भी इसका विनाशकारी परिणाम होना तय है।

एस.यू.सी.आई. (सी) की केन्द्रीय कमिटी का दृढ़ मत है कि आजादी के तुरन्त बाद भारत में गठित हुए राज्यों को बाद में बांट कर जो सब छोटे-छोटे राज्य बनाये गये—जिसकी ताजा मिसाल हैं झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड—वहाँ जनजीवन के किसी भी क्षेत्र में पूँजीवादी जुल्म से जनता को लेशमात्र भी राहत नहीं मिली है। आंध्र प्रदेश को बांट कर जिस नये राज्य के गठन की घोषणा की गई है वहाँ की जनता का भी यही हश्र होगा। क्योंकि अभाव, दुख-तकलीफ, दुर्दशा का मूल कारण जो शोषणमूलक पूँजीवादी व्यवस्था है वह नये राज्य के गठन से बदल नहीं जाएगी।

इस प्रकार राज्य का बंटवारा या यहाँ आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करने का फायदा उठायेगे केवल मुट्ठी भर सत्ताधारी राजनीतिज्ञ, उच्च स्तर के अफसरशाह और प्रशासनिक कर्ताधर्ता, जो नये राज्य के सिरमौर बन कर उसी तरह स्वेच्छाचारी तौर-तरीके से शासन करेंगे। इसके अलावा, आकाशछूती महंगाई, विकराल रूप लेती बेरोजगारी, छत्ती-कारखानाबंदी, किसानों की लगातार हो रही बढहाली आदि समस्याएं मेहनतकश जनता को पहले की तरह ही सताती रहेंगी, बल्कि उनके कंधों पर नया राज्य बनाने के लिए भारी आर्थिक बोझ लाद दिया जाएगा।

आगामी लोकसभा चुनावों में सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ाने की खातिर शासक कांग्रेस द्वारा लिया गया यह घृणित फैसला पूरे देश में मौजूद अलगाववादी, विछिन्नावादी ताकतों को और भी बल प्रदान करेगा और भ्रातृघाती झगड़ों को हवा देगा, जिसके फलस्वरूप जाति-धर्म-वर्ण-भाषा-सम्प्रदाय आदि का भेदभाव किये बिना शोषित जनता का एकजुट जनआन्दोलन गठित व विकसित करने के रास्ते में जबरदस्त रुकावट पैदा करेगा। इसलिए आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र की जनता से पार्टी की केन्द्रीय कमिटी का हार्दिक निवेदन है कि वे शासक पूँजीपति वर्ग के घृणित फंदे में न फँसें, धीरज और शान्ति के साथ तमाम अहम पहलुओं पर विचार करें और रायलसीमा व आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों की जनता के साथ एकजुट रहते हुए इस साजिश के खिलाफ उठ खड़े हो कर जीवन की समस्याओं के निराकरण की मांग पर एकताबद्ध जनआन्दोलन गठित करने के रास्ते पर आगे बढ़ें। केन्द्र सरकार से केन्द्रीय कमिटी इस विनाशकारी फैसले को तुरन्त रद्द करने की मांग करती है और आंध्र प्रदेश की जनता से इसी मांग को बुलन्द करने का आह्वान करती है।

कॉमरेड शिवदास घोष ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

पार्टी के पंजाब राज्य प्रभारी काँ. अमीन्दर पाल सिंह ने की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में पार्टी के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं व समर्थकों से मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष चिंतन से लैस होकर जनता को संगठित करने तथा उसे आंदोलन के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। उन्होंने गदर आन्दोलन का शताब्दी वर्ष गाँव स्तर पर मनाने की भी बात कही। काँ. जगतार सिंह और इन्द्रजीत जोधा ने भी सभा को सम्बोधित किया। सभा का संचालन काँ. इन्द्र सिंह ने किया।

हरियाणा

रोहतक : 9 अगस्त को छोटाराम पार्क स्थित सभागार में अपने दिवंगत नेता, एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) के संस्थापक महासचिव, इस युग के महान् मार्क्सवादी चिन्तनकार काँ. शिवदास घोष की 37वीं बरसी पर एक राज्य स्तरीय स्मृति सभा की गई। सभा की अध्यक्षता पार्टी की केन्द्रीय कमिटी के सदस्य और हरियाणा राज्य कमिटी के सचिव काँ. सत्यवान ने की। इस मौके पर पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य काँ. कृष्ण चक्रवर्ती मुख्य वक्ता रहे। सभा में घोषणा की गई कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 8 अक्टूबर को रोहतक में एक विशाल विरोध रैली की जाएगी।

राज्य भर में पहले जिला स्तर पर काँ. शिवदास घोष स्मृति सभाएँ की गईं। 1 अगस्त को जाट धर्मशाला, कुरुक्षेत्र में हुई स्मृति सभा की अध्यक्षता पार्टी के जिला सचिव काँ. रोशनलाल ने की। 2 अगस्त को कुम्हार धर्मशाला, सोनीपत में हुई स्मृति सभा की अध्यक्षता पार्टी के जिला सचिव काँ. इश्वर सिंह राठी ने की। 3 अगस्त को सेनी चौपाल, गुडगाँव में हुई स्मृति सभा की अध्यक्षता पार्टी के जिला सचिव काँ. श्रवण कुमार ने की। 4 अगस्त को छोटाराम धर्मशाला, झर्रज में हुई सभा की अध्यक्षता पार्टी के जिला सचिव काँ. अनूप सिंह ने की। 7 अगस्त को श्रीचेतराम प्रजापति धर्मशाला, भिवानी में पार्टी के जिला सचिव काँ. रामफल की अध्यक्षता में स्मृति सभा हुई। 11 अगस्त को बाल भवन, रेवाड़ी में स्मृति सभा की गई जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला सचिव काँ. राजेन्द्र सिंह ने की। सभाओं में मुख्य वक्ता थे एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) की केन्द्रीय कमिटी के सदस्य और हरियाणा राज्य कमिटी के सचिव काँ. सत्यवान।

उन्होंने कहा कि सर्वहारा के महान् नेता कॉमरेड शिवदास घोष का सबसे बड़ा योगदान यह है कि सीपीआई के मौजूद रहते हुए भी चूँकि भारत में कोई सही कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी, अतः उन्होंने अप्रैल 1948 में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की स्थापना की और सभी कष्टसाध्य संघर्ष करते हुए इसे इतना पृष्ठपोषित व मार्गदर्शित किया कि यह आज देश के लगभग सभी राज्यों के लोगों में गहरी जड़ें जमा चुकी है। यह पार्टी मेहनतकश जनता को उन्नत सर्वहारा संस्कृति से लैस कर जगा रही है, उसे संगठित कर जनजीवन के ज्वलंत मुद्दों पर जनआन्दोलन कर रही है। पार्टी के बढ़ने की जबरदस्त संभावनाएँ खुल रही हैं। मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष चिन्तनधारा न केवल भारतीय बल्कि विश्व क्रान्ति की राह रोशन कर सकती है और जनता को पूँजीवादी शोषण-जुल्म से निजात दिला सकती है।

बिहार

पटना : सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष के 37 वें स्मृति दिवस पर स्मृति सभा का आयोजन 5 अगस्त को पटना के आई.एम.ए. हाल में हुआ। सभा के मुख्य वक्ता थे पार्टी के केन्द्रीय कमिटी सदस्य और हरियाणा राज्य सचिव काँ. सत्यवान। सभा की अध्यक्षता पार्टी के बिहार राज्य सचिव काँ. शिव शंकर ने की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में पार्टी के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं व समर्थकों से मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष चिंतन से लैस होकर जनता को संगठित करने तथा उसे आंदोलन के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। राज्य कमिटी के वरिष्ठ सदस्य काँ. अरुण कुमार सिंह ने कहा कि देश और बिहार में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, रेप-गैंगरेप भयंकर रूप लिये हुए हैं। कांग्रेस, भाजपा, जदयू, राजद सहित तमाम बुजुआ पार्टियों से जनता उब चुकी है। सीपीआई और सीपीआई(एम) भी इससे इतर नहीं है।

मुख्य वक्ता काँ. सत्यवान ने अपने संक्षिप्त भाषण में कहा कि यह 5 अगस्त का दिन इस देश के क्रान्तिकारियों के लिए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के नेता-कार्यकर्ताओं



रोहतक में स्मृति सभा को संबोधित करते हुए काँ. कृष्ण चक्रवर्ती

और इसको मानने वाले और चाहने वालों के लिए जहाँ एक दर्द भरा दिन है, वहीं प्रेरणा का दिन भी है। 37 वर्ष पहले इस दिन हम सबके प्रिय नेता, शिक्षक, पथ प्रदर्शक भारत की क्रांति को राह दिखाने वाले शास्त्र और महान हस्ती काँ. लेनिन के जमाने के बाद से सबसे योग्य मार्क्सवादी चिन्तनकार दार्शनिक काँ. शिवदास घोष हमारे बीच से चले गए। लेकिन अपनी आखरी साँस तक भारत की शोषित-पीड़ित जनता को, उनके संघर्षों को और विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन को जो राह उन्होंने दिखायी, जिस महान संघर्ष को उन्होंने अपने जीवन में छेड़ा वह हमारे सामने है। उनकी सीखें, उनके क्रांतिकारी विचार हमारे बीच में हैं। हममें बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्हें काँ. शिवदास घोष से मिलने का अवसर नहीं मिला। काँ. शिवदास घोष जिन्होंने आजादी आंदोलन में और आजादी आंदोलन के बाद इस देश की नई क्रांति समाजवादी क्रांति का सूत्रपात करने के लिए जो संघर्ष किया इसके लिए हमारी आने वाली पीढ़ियों तक वे याद किये जायेंगे। लेकिन हम क्यों याद कर रहे हैं? हम याद कर रहे हैं इसलिए कि उनको जो चाहत थी, हम उनके जैसे बन, उनके पद चिन्हों पर चलें, जिस मकसद से वे आखरी क्षण तक संघर्षरत रहे वह अभी भी पूरा नहीं हुआ है। भारत की गरीब, शोषित जनता भारत की क्रांति को पूरा करने के मकसद में अपने को शामिल करें। जिस तरह काँ. घोष ने बचपन से ही आजादी आंदोलन में भाग लिया, अपने युवा काल में भारतीय क्रांति की जिम्मेवारी अपने कंधे पर ली। हम भी अपने जीवन में उसी तरह जिम्मेवारी को लें और उनके क्रांतिकारी सीखों व क्रांतिकारी विचारों को जन-जन तक ले जाएँ, देश के कोने-कोने में ले जाएँ। क्या हम यह कार्य कर सकते हैं? इसके लिए अपने जीवन को बदल सकते हैं? इसके लिए अपने जीवन को संघर्षशीलता को तेज कर सकते हैं? जनता पर जहाँ भी अत्याचार हो रहे हैं, वे लड़ रहे हैं वहाँ क्या हम उनके बीच वाणी दे सकते हैं? जहाँ भी लोग इस पूँजीवादी शासन-शोषण से दो-चार हो रहे हैं उनके बीच में काँ. घोष की सीखों को क्या ले जा सकते हैं? अगर यह कर सकते हैं और यह करते हुए स्वयं को एक अच्छे योग्य कार्यकर्ता में, एक योग्य कार्यकर्ता से जनता को हर स्तर पर अगुआई करने वाले एक संगठनकर्ता के रूप में अपने आप को तब्दील कर सकते हैं तब निश्चित रूप से काँ. घोष के प्रति सच्ची श्रद्धांजली होगी।

इस रास्ते पर बढ़ने का जो संकल्प हमने लिया था उसे आज फिर तरोताजा करने का दिन है। काँ. घोष एक ऐसी हस्ती थे जिनमें दो चीजों का महान मिलन हुआ है, चिंतन और कर्म का। ऐसे शास्त्र किसी देश में, दुनिया में बिरले होते हैं। मार्क्स से शुरू करके उनके सहयोगी एंगेल्स, महान लेनिन उनके सहयोगी व काबिल शिष्य स्टालिन, चीन की क्रांति को साकार करने वाले महान माओ त्से-तुंग और इन सभी के काबिल, योग्यतम शिष्य भारत की क्रांति के सूत्रधार काँ. शिवदास घोष के जीवन में एक सुयोग्य क्रांतिकारी चिन्तनकार और एक सुयोग्य क्रांतिकारी संगठनकर्ता, अर्थात् चिंतन और कर्म एक जगह आकर एक दूसरे से मिलकर एकाकार हो गया— ऐसे थे वे। एक सभा में उनके जीवन को समझना संभव नहीं है। हमें और भी गहराई से और भी लगन से साधना के साथ वहाँ तक पहुँचना होगा।

जिस आर्थिक संकट की घड़ी में हम यह स्मृति सभा कर रहे हैं, नजर उठाकर देखें पूरे हिन्दुस्तान की और बिहार की स्थिति क्या है? जो कमेरी जनता हर चीज पैदा करती है—सिर्फ चीजों को ही नहीं बल्कि ज्ञान को भी पैदा करती है—वे मेहनतकश लोग, मजदूर-किसान किस कदर शोषण, अन्याय, अत्याचार, तरह-तरह के भेदभाव और भ्रष्टाचार के शिकार हैं। आज देश में जो पूँजीपतियों का शासन है और जिस तरह की नीतियों पर भारत सरकार और अलग-अलग राज्य की सरकारें व बिहार राज्य की भी नीतीश सरकार चल रही है, उसी का नतीजा है कि जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरी करने

वाली सेवाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, रेल सेवाएँ इन सबको मुनाफा लूटने का जरिया बना दिया गया है। आज देश का नौजवान बेरोजगारी से जुझ रहा है। हर घर-परिवार में काबिल लड़के-लड़कियाँ योग्यता-सामर्थ्य होते हुए भी रोजगार से वंचित हैं। जिस मनरेगा की इतनी दुहाई दी जाती है इसमें हर राज्य में घोर भ्रष्टाचार तो है ही, साथ-साथ सरकारों का रवैया ऐसा है कि खुद सरकार देहात में चालू मजदूरी की दर से भी मजदूरी नहीं देती है। आज यह देहात का गरीब, गरीबी रेखा से नीचे कहकर जो उनकी सूची बनायी जाती है उसमें नाम लिखाने के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं। उन्हें रहने के लिए घर नहीं है। वे घर-प्लाट के लिए तरस रहे हैं। सरकार द्वारा गरीबी का निर्धारित पैमाना सुनकर देश के लोग दंग हैं। योजना आयोग में बड़े-बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि जो देहात में 28 रु. से कम रोजाना कमाते हैं वे ही हैं गरीब और जो इससे ऊपर कमाते हैं वे हैं अमीर, साहूकार। शहरों (पटना, मुजफ्फरपुर आदि) में जिनकी आमदनी रोजाना 33 रु. हो वे होंगे अमीर। कांग्रेस के नेता निलंजिता के साथ कह रहे हैं कि किसी भी शहर में एक रुपये में खाना मिल सकता है। फिल्मों से निकलकर वे लीडर बने हैं। वे कह रहे हैं कि मुंबई जैसे शहरों में जो देश का सबसे महंगा शहर है वहाँ 12 रु. में भरपेट खाना मिल सकता है। कांग्रेसी नेता का भी कहना है कि 5 रु. में भरपेट खाना मिल सकता है।

आज स्थिति क्या है? किसी भी राज्य में जाएँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के शरीर में खून नहीं है। हमारे परिवार की अधिकांश महिलाएँ खून की कमी की शिकार हैं। 100 में से 86 महिलाएँ एनिमिया की शिकार हैं। यह रोग किसी कीटाणु से पैदा नहीं होता। यह रोग भूखों रहने से होता है। पशु भी सिर्फ भूसा नहीं खा सकता। उसे भी भूसे के साथ कुछ चाहिए। मनुष्यों को भोजन में अनाज के अलावा दूध, दाल, सब्जी, फल भी चाहिए, नहीं तो कुपोषण के शिकार हो जायेंगे। सरकार का एक ही काम बचा है वह यह कि डीजल-पेट्रोल, रसाईं गैस का दाम बढ़ा दो, बिजली का दाम बढ़ा दो, खाद का दाम बढ़ा दो, नया कानून बनाकर उनके बच्चे-खुचे अधिकार छीन लो। यही हर सरकार का पेशा हो गया है। हर सरकार अरबों-खरबों का घोटाला कर रही है। फैक्ट्रियों में मजदूरों का भयंकर शोषण किया जा रहा है। फैक्ट्रियों से मजदूरों को नौकरी से निकाला जा रहा है। कहीं कोई स्थायी नौकरी नहीं है, हर जगह ठेका प्रथा है। आज हर सरकार कारपोरेट घरानों के लिए, कर्पणियों के लिए किसानों की जमीन छीन रही है, जो जमीन देश के 100 लोगों में से 60 को रोजी-रोटी देती है। उन्हें जमीन चाहिए 10 एकड़ मगर खरीदते हैं कौड़ियों के भाव सस्ती दर पर हजारों एकड़। फिर वही मालिक उस जमीन को वापिस बेचते हैं कई गुना महंगे दामों पर। हर प्रांत की सरकार, वह चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या किसी गठबंधन की, सभी सरकारें यही कार्य कर रही हैं।

इस देश की नकली कम्युनिस्ट पार्टियाँ जो पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा जहाँ लंबे असें तक शासन में रही हैं या फिलहाल हैं वे भी किसानों के साथ यही बर्ताव कर रही हैं। बल्कि कांग्रेस-बीजेपी से भी आगे बढ़कर इन्होंने सिंगूर में, नंदीग्राम में किसानों पर जुल्म दिये हैं। देश का कोई भी कोना बाकी नहीं है जहाँ दूध-मुँही बच्ची से लेकर दादी-नानी के उम्र की बुजुर्ग महिलाओं की इज्जत और जीवन पर हमले नहीं हो रहे हैं। क्या यही समाज है? किसने बनाया ऐसा? जिस गाँधीजी का नाम लेकर ये लोग लूट मचा रहे हैं, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा था। आज पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन शराब का इंतजाम किया हुआ है। नौजवानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए, उनके चरित्र को गिराने के लिए, उनके नैतिक बल को तोड़ने के लिए, छात्रों-नौजवानों को पथभ्रष्ट करने के लिए क्या इंतजाम इन्होंने नहीं किया।

काँ. घोष खुद आजादी आंदोलन के एक सिपाही थे, एक कर्मी थे। उन्होंने हिन्दुस्तान की जनता से क्या कहा

(शेष पृष्ठ 5 पर)

व्यक्तिगत हत्याएं और क्रांतिकारी राजनीति

पिछले कुछ समय से व्यक्तिगत हत्याओं, सार्वजनिक स्थानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सिलसिलेवार बम धमाकों, रेल की पट्टियों व पुलों को उड़ा देने, भीड़ भरी बसों में गोलियों की बौछारों और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर घात लगाकर किये गये हमलों की घटनाओं में उछाल आया हुआ है जिनमें विशेष टारगेटों के अलावा भारी संख्या में बेगुनाह लोगों की जान भी चली जाती है। हत्या और हिंसा के तमाम ऐसे घृणित कृत्यों के पीछे कथित तौर पर विभिन्न आतंकवादी गुप्तों, अलगाववादी-विछिन्नतावादी साम्प्रदायिक गुप्तों का हाथ होता है। विशेष अवसरों पर ऐसे कुछ गुट इस प्रकार के घन्य कृत्यों को अंजाम देने का दावा करते हैं। इन तमाम घटनाओं में बेरहम पूँजीवादी शोषण की चक्की में पिसते अभाग आम लोग ही हैं जो इसका खामियाजा भरते हैं। वे या तो मारे जाते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, सम्पत्ति का नुकसान, उत्पीड़न और यातना सहते हैं और किसी भी समय किसी भी दिन कहीं भी ऐसे विवेकहीन उन्मादों, कातिलाना हमलों और सुनियोजित हिंसा के शिकार बन जाने का खौफ उन पर लगातार छाया रहता है। हाल ही में, जो खुद को 'माओवादी' कहते हैं वे भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाये गये हैं। गत 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ में बस्तर सुकमा राजमार्ग पर लगभग 20 गाड़ियों के एक काफिले पर लगभग 150 लोगों के एक हथियारबंद गिरोह ने हमला कर दिया था और शासक पार्टी के कुछ नेताओं व सुरक्षा कर्मियों के अलावा लगभग 20 गरीब आदिवासी नागरिकों की भी हत्या कर दी थी। चंद्र दिनों के अन्दर ही बिहार के पटना से 170 कि मी दूर जमुई जिले में रेल के एक डिब्बे में हुए बम विस्फोट ने 3 आम मुसाफिरों की बेशकीमती जान ले ली थी। आपको याद होगा कि 3 साल पहले जब छत्तीसगढ़ के दातेवाड़ा जिले में कुछ स्पेशल पुलिस अफसरों को लेकर जा रही बस पर हमला किया गया तो बहुत से बेगुनाह मुसाफिरों समेत 40 लोग मौके पर ही मारे गये थे। उसी साल हावड़ा-मुम्बई ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस गाड़ी पश्चिम बंगाल में झाड़ग्राम के नजदीक हुई तोड़फोड़ की वजह से पटरी से उतर गई थी और इसमें 140 बेगुनाह मुसाफिरों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गये थे। आतंकियों, बागियों और राष्ट्र-विरोधी गुप्तों के सफाये के नाम पर राज्य के सुरक्षा बलों द्वारा छोड़े गए बदतरीन किस्म के काऊटर-टेरिज्म (आतंकवाद-विरोध) का दश भी लोगों को ही झेलना पड़ रहा है। उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जहाँ उत्पीड़ित और लुटे-पिटे लोग अपनी जान-माल पर लगातार जारी हमले के इस खतरे को समझने में ज्यादा से ज्यादा कठिनाई महसूस कर रहे हैं, वहीं सही सोच रखने वाले लोग भी हैरान हैं कि कैसे मार्क्सवाद के नाम पर और लाल झंडा लहराते हुए इस प्रकार की कार्रवारपूर्ण और क्रूर करतूतों को अंजाम दिया जा सकता है।

असहनीय दुख-तकलीफों का मंजर

आतंक और खौफ का साया जनता पर ऐसे समय छाया है जब उनके जीवन का हर क्षेत्र आर्थिक-राजनैतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक असहनीय दुख-तकलीफों से घिरा हुआ है और तीव्र अधःपतन का शिकार है। आकाशछूती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, भारी रोजगार हानि, कृषि उपजों-फसलों का लाभकारी मूल्य न मिलना, घटती आमदनी और बढ़ती वित्तीय बर्बरता ने उनके आर्थिक जीवन को जकड़ लिया है। संघर्षों से अर्जित तमाम जनवादी अधिकारों और राजनैतिक अधिकारों को एक-एक करके छीना जा रहा है, प्रतिवाद की आवाज का गला घोंटा जा रहा है। जरा सी भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाएं, पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। भुखमरी से मौतें, आत्म हत्याएं, कुपोषण, अपराध और महिलाओं पर अत्याचार में बढ़ोतरी, महिलाओं और बच्चियों की तस्करी, यौन-विकृति, नशे की लत, सर्वव्यापक भ्रष्टाचार, सूक्ष्म अनुभूतियों व मानवीय गुणों का तीव्र हास सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में तीव्र गिरावट को दर्शाते हैं। वंचना, नकारना, उत्पीड़न, न्याय न मिलना, हर स्तर पर परेशान और प्रताड़ित किया जाना जीवन को असल में दुस्वप्न बनाता जा रहा है। लेकिन यह बढ़ती हुई दुर्दशा और दरिद्रता, कंगाली और बदहाली न तो दैवी प्रकोप है और न ही भाग्य का लेखा। इसका कारण मानव द्वारा मानव के शोषण पर आधारित मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था में निहित है। तमाम बुराइयों, व्याधियों और विषयगमन, तकलीफों और दुर्दशा

इस निर्दयी दमनात्मक व्यवस्था द्वारा पैदा की गई हैं। पूरा का पूरा सामाजिक-राजनैतिक ढाँचा शासक पूँजीपतियों के घृणित वर्ग स्वार्थ की पूर्ति के लिए डिजाइन किया गया है जो शोषित-पीड़ित जनता को लाशों पर साम्राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए जन-जीवन की इस दमघोंटू परिस्थिति से निजात पाने का सवाल क्रान्ति के जरिये इस सड़े-गले पूँजीवाद को उखाड़ फेंकने के साथ आंत-प्रांत रूप से जुड़ा हुआ है। इस पूँजीवाद-विरोधी क्रान्ति को सम्पन्न करने के लिए लाजिमी है कि मेहनतकश जनता में क्रान्तिकारी चेतना का संचार हो, सही क्रान्तिकारी विचारधारा से वह लैस हो और सही क्रान्तिकारी नेतृत्व के तहत वर्ग संघर्ष व जनआन्दोलनों को तेज करने के क्रम में क्रान्तिकारी संघर्ष गठित करे। उत्पीड़ित जनता में कहीं इस क्रान्तिकारी चेतना का संचार न हो जाए और वह क्रान्तिकारी आन्दोलन में न कूद पड़े, इसलिए शासकों की तरफ से सुनियोजित साजिश रची जा रही है ताकि उनको मानसिक और सांस्कृतिक तौर पर पंगु बना दिया जाए, उनमें सामाजिक विमुखता पैदा कर दी जाए, तमाम तरह की विभाजनकारी मानसिकताओं और विकृत मनोवृत्तियों को उकसा कर उनमें फूट डाल दी जाए, संसदीय भ्रमजाल में उन्हें फंसा कर रखा जाए, उन्हें कट्टरता या भाग्यवाद की अधभक्ति का शिकार बना दिया जाए और सबसे बढ़ कर, उनमें नीच प्रवृत्तियों को भड़का कर उन्हें अनैतिक धंधों की दुनिया में धकेल दिया जाए ताकि उनकी नैतिक रीढ़ टूट जाए और उनका अस्तित्व पशुवत हो कर रह जाए जिनमें प्रतिवाद और विरोध करने का दमखम ही न रहे। यह है मरते हुए पूँजीवाद का आडम्बरपूर्ण षडयंत्र! **बुर्जुआ वर्ग स्वार्थ की हितसाधक ताकतें और सोशल डेमोक्रेट मर रहे लोगों का बंधक बनाए हुए हैं**

लेकिन यह सच्चाई लोगों के सामने उजागर नहीं हो रही है। क्योंकि विभिन्न क्रान्ति-विरोधी ताकतों की गतिविधियों वांछित वर्ग संघर्ष और जनआन्दोलन के विकास के सामने गंभीर बाधाएं खड़ी कर रही हैं, वे विभिन्न पथ भटकने वाले पैतरे अपना कर लोगों को गुमराह कर रही हैं। इनमें से कुछ ताकतें ऐसा जानबूझ कर कर रही हैं जबकि कुछ अन्य क्रान्ति, क्रान्तिकारी विचारधारा और क्रान्तिकारी प्रक्रिया की गलत समझ से संचालित होने की वजह से खेल बिगाड़ने के काम में लगी हुई हैं।

शासक पूँजीपति वर्ग की बेहद भरोसेमंद प्रतिनिधियों में से एक कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय बुर्जुआ पार्टियाँ जैसे टीएमसी, डीएमके, एआईडीएमके, बीएसपी, एसपी, बीजेडी, टीडीपी, अकाली, इनेलो, हजका या शिवसेना यह प्रचार करके लोगों को गुमराह करती हैं कि अगर चुनावों के जरिये उन्हें सत्ता में बिठा दिया जाए तो जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शासक वर्ग की एक और बेहद भरोसेमंद एजेण्ट और अपने जहरीले साम्प्रदायिक चरित्र के लिए मशहूर बीजेपी भी इसी तरह के झूठे वायदों और झांसा से लोगों को ठगती है। उनका एकमात्र सरोकार है वोट बैंक तैयार करना और लोगों को बुर्जुआ चुनावी राजनीति की चारदिवारी के अन्दर बांधे रखना। ज्यादा नुकसानदेह भूमिका तो सीपीआई(एम), सीपीआई जैसे नकली मार्क्सवादियों द्वारा निभाई गई है। मार्क्सवाद का जन्म पहने, खास सोशल डेमोक्रेटों के रूप में वे श्रम और पूँजी, शोषक और शोषित के बीच समझौते की भूमिका अदा करने में लिप्त हैं, वर्ग संघर्ष की जगह वर्ग समन्वय के सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं, संघर्षरत मजदूर-किसानों को अन्दर से कमजोर कर रहे हैं और इस तरह चालाकी से शासक पूँजीवाद का पर्दाफाश होने से बचा रहे हैं। अगर कोई नजदीक से उनके प्रवचनों, राजनैतिक पैतारों, कदमों, योजनाओं, कार्यक्रमों, मंचीय भाषणों और सबसे बढ़ कर सरकार चलाने के उनके नजरिये को देखें तो साफ हो जाएगा कि उनकी राजनीति का मर्म चुनाव है, जनता के बीच चुनावी मानसिकता पनपाना है, चुनावी जोड़-तोड़ करना है और चुनावी फायदा उठाने के लिए इस या उस बुर्जुआ पार्टी या गठबंधन से हाथ मिलाने की संभावनाओं को तलाशना है। ठीक दूसरी किसी वोट बटोरू बुर्जुआ पार्टी की तरह ही सीपीआई(एम), सीपीआई नेतागण सिर्फ चुनावी मोहजाल बढ़ाने में ही व्यस्त हैं ताकि लोगों का संचित गुस्सा और आक्रोश क्रान्तिकारी संघर्ष के लिए सहायक सही जनवादी आन्दोलन की उफनती लहरों में अभिव्यक्ति पाने की बजाय इसका अंत बैलट पेपर पर ठप्पा लगाने में हो जाए और

उनको चुनावी फायदा पहुँचाये। शासक पूँजीपति वर्ग को इतनी मूल्यवान सेवा प्रदान करने और लोगों की पीठ में छुरा घोंपने के एवज में नकली मार्क्सवादियों को पूँजीपति वर्ग का भरपूर समर्थन मिलता है, इसकी उदारता के चलते राजनैतिक मुख्यधारा में 'अधिकृत वामपंथियों' का दर्जा उन्हें हासिल है और इनकी मेहरबानी से धन-दौलत और सत्ता का सुख भोग रहे हैं। इसी वजह से महान मार्क्सवादी अर्थोरीटियों ने कहा था कि अब सोशल डेमोक्रेट ही पूँजीवाद का आखिरी अवलंब हैं और सोशल डेमोक्रेटिज्म का खाल्टा किये बिना पूँजीवाद का खाल्टा करना नामुमकिन है।

शासक पूँजीपति वर्ग के प्रति निष्ठावान अलगाववादी-विछिन्नतावादी-संकीर्णतावादी-अंधराष्ट्रवादी ताकतें भी शोषित-पीड़ित लेकिन अर्नभिन्न लोगों को जनवादी आन्दोलन और क्रान्तिकारी संघर्ष के रास्ते से भटकाने के धिनौने खेल में पीछे नहीं हैं। वे लोगों के एक विशेष समुदाय या तबके के लिए मुक्ति की और सशस्त्र संघर्ष, नस्ली सफाये, विवेकहीन हत्या और हिंसा के जरिये उनकी तमाम ज्वलंत समस्याओं के समाधान की बात करते हैं। बाहर देखने पर लगता है कि वे संसदीय चुनावी राजनीति को नकार रहे हैं और अपनी माँगें हासिल करने के लिए संघर्ष का रास्ता अखिर्यार करने की खातिर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन उनके भी निशाने पर शैतान पूँजीवाद नहीं होता है बल्कि वे गोपनीय तरीके से इसे छिपाते हैं और इसकी बजाय मेहनतकश जनता के एक तबके को जो समान रूप से बर्बर पूँजीवादी शोषण से आक्रांत हैं और बदहाल हैं, उसे दूसरे तबके के दुश्मन के रूप में पेश किया जाता है। वे लगातार मनो में जहर भरने, लोगों के एक तबके को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने, आपसी झगड़े-फसाद में उलझाने, बेगुनाहों का खून बहाने और इस तरह मेहनतकश जनता की एकता में दरार डालने के काम में लिप्त रहते हैं जबकि शासक पूँजीवाद जो जाति, धर्म, वंशमूल, सम्प्रदाय, क्षेत्र या भाषा का भेदभाव किये बिना सब मेहनतकश लोगों के जीवन में तबाही ला रहा है वह अछूता ही रह जाता है। अलगाववादी गुप्त भी भारतीय राष्ट्र से अलग होने और नया राष्ट्र कायम करने की अपनी माँग को खातिर हिंसा और आतंक के बल पर लोगों को घुटने टेकने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए एक-दूसरे का खून बहाने का पागलपन, अपने ही भाइयों और पड़ोसियों को कत्ल करना, वंशमूलगत-साम्प्रदायिक नफरत और विद्वेष गहरा देना और फूटपरस्त संगठनों के बहुत से नेताओं और कैडरों के जीवन का भी समय से पहले अंत होना जारी है लेकिन लोगों की एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है बल्कि समस्याएं और भी गहरा गई हैं। इसके विरत पूँजीवादी शासकों और उनकी सरकारों की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ उत्पीड़ित जनता के सभी तबकों का संयुक्त संघर्ष गठित करने की अहम जरूरत को जबरदस्त आघात लगा है। स्वाभाविक है कि शासक पूँजीपति वर्ग इस या उस बहाने उत्पीड़ित जनता के बीच लगातार फूट डालने की अपनी साजिश को अंजाम देने में इन फूटपरस्त ताकतों को नितांत उपयोगी पा रहा है ताकि इसके शोषणमूलक शासन के खिलाफ जनसंघर्ष के उभरने की संभावना का गला घोंटा जा सके। इसलिए शासक वर्ग भी बहुत ही शातिराना ढंग से ऐसी ताकतों को मदद देता है। देश का उत्तर-पूर्वी भग इस त्रासदी की जीती जागीति मिसाल है। **नक्सलवादी ताकतों और स्वोषित 'माओवादियों' की गतिविधियों के विनाशकारी परिणाम**

पूँजीवाद-विरोधी क्रान्ति में सहायक जनवादी जनआन्दोलनों का वांछित उभार जो मेहनतकश जनता के जीवन में कुछ राहत ला सकता है और क्रान्ति के जरिये सर्वव्याप्त संकट से अंतिम रूप से मुक्ति की जरूरत के बारे में धीरे-धीरे उन्हें जागरूक बना सकता है, 'नक्सलवादी' विचारधारा के पैरोकारों, खास कर जो खुद को 'माओवादी' या महान मार्क्सवादी अर्थोरीटि और चीनी क्रान्ति के सूत्रधार महान माओ त्से-तुंग के विचारों के अनुयायी बताते हैं इनकी गतिविधियों की वजह से वह भी गंभीर खतरे में पड़ गया है। आपको यह भी याद होगा कि 1960 के दशक के अंतिम में सीपीआई(एम) से टूट कर अलग हुए एक गुट सीपीआई(एमएल) द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी जब इसने चीनी क्रान्ति की रणनीति की अधी नकल करते हुए सत्ता पर कब्जा करने का आह्वान किया था और पुलिस व पैरा मिलिट्री के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया (श्रेष्ठ पृष्ठ 4 पर)

व्यक्तिगत हत्याएं और क्रान्तिकारी राजनीति

(पृष्ठ 3 का शेष)

था और 'वर्ग दुश्मनों' व जमींदारों के खामते' के नाम पर व्यक्तिगत हत्याओं में संलिप्त हुआ था। नक्सलवादी सिद्धांतकारों ने इस विश्वास का पोषण किया था कि ऐसी एक रणनीति और 'बहादुराना' कार्यवाहियों राजसत्ता के खिलाफ लड़ने में उत्पीड़ित लोगों को प्रोत्साहित करेगी और इस तरह वे क्रान्ति को अंजाम देने के लिए स्वतःस्फूर्त ढंग से आगे आ जाएंगे। लेकिन क्रान्ति की उनकी समझ या भारतीय परिस्थिति का उनका विश्लेषण सत्य से कोसों दूर होने की वजह से जिस नक्सलवादी आन्दोलन ने शुरूआत में कुछ हलचल पैदा की थी वह थोड़े ही दिनों में छिन्न-भिन्न हो गया। एक्शन के दौरान बड़ी संख्या में नक्सलवादी कार्यकर्ता मारे गये जबकि जो बच गए उनमें एक गहरी निराशा छा गई। उनके एक बड़े हिस्से ने सक्रिय राजनीति से किनारा कर लिया। दूसरा हिस्सा शासक पूँजीवाद का दुमछल्ला बन गया। पराजय का दोष एक-दूसरे पर मढ़ते हुए सीपीआई(एमएल) असंख्य टुकड़ों में बंट गई। इस पूरे घटनाक्रम ने जनसाधारण को भी काफी हद तक निराशा-हताशा किया, क्रान्तिकारी राजनीति के बारे में नकारात्मक सोच पैदा की और काफी हद तक उन्हें जनवादी आन्दोलन के रास्ते से परे धकेल दिया। नक्सलवादी अनिष्ट ने इस तरह न्यायसंगत जनवादी आन्दोलन के विकास की प्रक्रिया को बहुत भारी नुकसान पहुँचाया और दरअसल प्रतिक्रिया की ताकतों को ही मजबूत किया।

कुछ सालों के अंतराल के बाद जब पूँजीवादी शोषण-दमन और भी गहन हो गया, तब नक्सलवादियों के विच्छिन्न गुटों ने एक नया संगठन सीपीआई(माओवादी) बनाने के लिए हाथ मिलाया। इस नई पार्टी ने अपना संगठन कायम करने के लिए ग्रामीण भारत, खास कर छह भारतीय प्रांतों के भूभाग की कुछ चुनिंदा पॉकेटों को चुना जहाँ ज्यादातर निहायत गरीब और वंचित आदिवासी रहते हैं और इन अति पिछड़े लोगों के कुछ हिस्सों के बीच कुछ अनुयायी बना सके थे। अमानवीय अस्तित्व में धकेल दिये जाने और वंचना, अस्वीकृति-अवहेलना और हर कदम पर भेदभाव का शिकार होने के चलते ये बेचारे आदिवासी अन्दर से उबल रहे थे और स्वाभाविक तौर पर अमीरों और सम्पन्न लोगों के खिलाफ नफरत भी रखते थे। लेकिन समृद्ध तबके के खिलाफ यह नफरत की भावना कोई वर्ग चेतना नहीं है जिसे सही रास्ते पर संघर्ष की प्रक्रिया में हासिल करने की जरूरत होती है। लेकिन वर्ग चेतना क्या है, क्रान्ति का मतलब क्या है, कैसे यह पनपती है और ठोस परिस्थिति में क्रान्तिकारी आन्दोलन कैसे संचालित किया जाता है इन सबकी व्याख्या करने की कोई जहमत उठाये बिना ही, सीपीआई(माओवादी) नेताओं ने इन गरीब आदिवासियों को सिर्फ इतना ही समझाना मुनासिब समझा कि सिर्फ सशस्त्र संघर्ष के जरिये ही वे अपनी न्यायसंगत माँगों को हासिल कर सकते हैं, वंचना और दुख-तकलीफों से निजात पा सकते हैं। रणनीति के तौर पर उन्होंने पुलिस बल पर घात लगा कर हमला करने, पुलिस बैरकों और थानों पर हमले करने, जेलों और शस्त्रागारों को तोड़ने, सार्वजनिक स्थानों पर बम धमाके करने, कथित तौर पर रेल पटरियों को उड़ा देने, चुनिंदा व्यक्तियों की हत्या करने और बंधक बनाने, बैंक डकैतियों डालने, जबरन वसूली करने, लूट-पाट आदि में लिप्त होने का रास्ता अपनाया और इन्हें ही 'क्रान्तिकारी लड़ाइयों' के रूप में पेश किया। उन्होंने समर्थन जुटाने के साधन के तौर पर जातिवादी और वंशमूल के विभाजनों को इस्तेमाल करने को भी अनुचित नहीं समझा। सशस्त्र कार्यवाहियों के इस जाहिरा 'रोमांस' ने शुरूआत में बहुत से आदिवासी लड़के-लड़कियों को इस नये संगठन की तरफ आकर्षित किया जब तक कि यह अल्पकालिक 'कोतुहल' और 'उत्साह- ठंडा नहीं पड़ गया। उनमें से बहुत से इस बात में ईमानदारी से यकीन रखते थे कि यदा-कदा की हिंसा और व्यक्तिगत हत्या का घनीभूत होना अर्थोपरिष्ठियों को व्यवस्था का वांछित परिवर्तन ला देने वाली क्रान्ति के सामने झुकाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही यह खत्म हुआ, राजसत्ता अपनी दमनात्मक मशीनरी के साथ उन पर दृढ़ पकड़, खाना तलाशी तेज कर दी गई, नेता-कार्यकर्ता पुलिस-मिलिट्री की गोलियों की बौछार से ढेर हो गये, वे दबाव का मुकाबला नहीं कर पाये। उनमें हताशा का भाव भर गया। संगठन पूरी तरह तहस-नहस हो गया। 'सामान्य जीवन की ओर लौटने' के नाम पर नेताओं

सहित अनेक कार्यकर्ताओं का प्रशासन के सामने दबू समर्पण ज्यादा से ज्यादा तादाद में सामने आने लगा। इसके अलावा, चूँकि दीर्घस्थायी जनआन्दोलन और वर्गसंघर्ष के तजुबों और सबकों के जरिये सीपीआई(माओवादी) द्वारा आम लोगों के व्यापक तबकों को संगठित नहीं किया गया था, वे इस पार्टी के साथ तब तक जुड़े रहे जब तक कि वह उनकी जरूरी माँगें उठाती रही। इस तथ्य को अच्छी तरह जानते हुए कि 'माओवादी' कैडरों और बाहर से समर्थन दे रही जनता में क्रान्तिकारी चेतना और चरित्र का अभाव है और वे तो इस दुस्साहसिक कार्यवाही में सिर्फ इसलिए शामिल हो गये कि उनको मूलभूत आवश्यकताओं का न्यूनतम भी उपलब्ध नहीं है, सरकार-प्रशासन ने भी उनके सामने कुछ टुकड़े फेंकते हुए चालाकी से अपना 'विकास' का पत्ता खल दिया। शासनतंत्र ने जब कठोर दमनात्मक कदमों के साथ-साथ विकास का चारा फेंका तो स्वधोषित 'माओवादी' आन्दोलन के लिए लोगों का आकर्षण विकर्षण में बदल गया, सहानुभूति की जगह बेरुखी ने ले ली। 'माओवादी' पाठों में अनेक 'लाभों की खेरात बाटने' के ऐसे दिखावटी प्रोग्रामों के अनुमोदक बन गए और यहाँ तक कि राजसत्ता के हाथों खुद को बेच दिया। इस प्रक्रिया में, आदिवासी जनता के एक बहुत बड़े हिस्से ने भी खुद को 'माओवादी' आन्दोलन से अलग-थलग कर लिया जिसने बुर्जुआ सरकारों को यह दावा करने का मौका दे दिया कि 'विकास' को आगे बढ़ा कर उन्हे 'माओवादी' विद्रोह को दबाने में कामयाबी हासिल कर ली है। क्रान्ति और क्रान्तिकारी संघर्ष के विकास की पद्धति की गलत समझ का यह एक परिणाम है।

क्रान्ति और भारतीय परिस्थिति की गलत समझ

सीपीआई(माओवादी) के नेताओं को क्या चीज जकड़े हुए है? आवेगरहित और बिना किसी पूर्वधारण या अंधता से ग्रसित हुए उन्हे आत्म निरीक्षण करना चाहिए यह देखने के लिए कि क्या वे वास्तव में ही माओ त्से-तुंग की शिक्षाओं का अनुसरण कर रहे हैं या नेक इच्छाओं और गरीबपरस्त मन के बावजूद उससे कोसों दूर हैं? क्या वे क्रान्ति के उद्देश्य को मद्दद पहुँचा रहे हैं या उसमें बाधा खड़ी कर रहे हैं? क्या वे सैद्धान्तिक प्रतिपादन में या व्यवहारिक प्रयोग में एक स्पष्ट विचार को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि क्रान्ति, क्रान्ति संगठित करने की प्रक्रिया का मतलब क्या है और मार्क्सवादी-लेनिनवादी विज्ञान में इतने साफ तौर पर सूत्रबद्ध क्रान्ति की वस्तुगत और भावगत परिस्थितियों को पूरा करने के अत्यावश्यक काम का निवाह करते हुए सही रास्ते पर क्रान्तिकारी संघर्ष गठित कर रहे हैं?

मार्क्सवाद-लेनिनवाद ही केवल लोगों को मुक्ति का रास्ता दिखा सकता है, इसके अनुसार क्रान्ति सिर्फ इसीलिए अपने आप नहीं हो जाएगी कि प्रचांड पूँजीवादी आक्रमण द्वारा लोगों का दमन-उत्पीड़न हो रहा है। वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हुए क्रान्ति को संगठित करना पड़ता है। दुख-तकलीफ और दमन जब बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो जाते हैं तब लोग मुक्ति के लिए व्यग्र हो उठते हैं और जब मौजूदा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था से उत्पन्न संकट इतना गहरा जाता है कि व्यवस्था ही अस्थिरता से डगमगाने लगती है तब समझा जाता है कि क्रान्ति की वस्तुगत परिस्थिति परिपक्व हो गई है। लेकिन अनुकूल वस्तुगत परिस्थिति का पैदा हो जाना स्वयमेव ही क्रान्ति को सफल नहीं बना देता है। भावगत परिस्थिति को भी पूरा करना पड़ता है और दोनों को एक साथ होना चाहिए। भावगत परिस्थिति के परिपक्व होने को पूर्वशर्त है, समाज के क्रान्तिकारी परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए मेहनतकश जनता द्वारा पर्याप्त तैयारी की जाए और अनुकूल मनोभाव पैदा किया जाए। लेनिनवादी मॉडल पर गठित और जीवन के तमाम पहलुओं को समेटे हुए सही क्रान्तिकारी सिद्धांत से लैस एक सही क्रान्तिकारी पार्टी ही लोगों को राजनैतिक चेतना को इस स्तर तक उठा सकती है और कक्षासाध्य सैद्धान्तिक संघर्ष के जरिये विशाल जनता को क्रान्ति का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है, वर्ग संघर्ष और जन संघर्षों में उन्हे तपा कर फौलादी बना सकती है और क्रान्ति के हक में निर्णायक रूप से उनका समर्थन जुटा सकती है। क्रान्तिकारी पार्टी, सही क्रान्तिकारी सिद्धांत के साथ जनता को क्रान्ति की ओर प्रेरित करने में सफल हो जाती है तो यह पूँजीवादी राजसत्ता की भाड़े की फौज का मुकाबला करने में सक्षम एक सशक्त क्रान्तिकारी जन सेना (पीपुल्स आर्मी) को जन्म देती है, क्रान्ति को नेतृत्व देने के लिए सैद्धान्तिक और सांगठनिक दोनों तरह से पर्याप्त ताकत हासिल कर लेती है तब कहा जाता है कि क्रान्ति के लिए भावगत

परिस्थिति परिपक्व हो गई है। इसलिए यह देखा जा सकता है कि भावगत परिस्थिति तैयार करने के लिए लेनिनीय मॉडल पर आधारित एक सही क्रान्तिकारी पार्टी का निर्माण, सही क्रान्तिकारी सिद्धांत और सही मूल राजनैतिक लाइन पूर्वशर्तें हैं। क्या इन पूर्वशर्तों को सीपीआई(माओवादी) द्वारा पूरा कर लिया गया है? जवाब है नहीं। धुंधले नक्सलवादी तत्वों से मिल कर बने पूर्ववर्ती सीपीआई(एमएल) के दो विच्छिन्न गुटों के विलय की घोषणा से इसका निर्माण हुआ था। सिर्फ शुभेच्छा पर आधारित संकल्प, सही तौर पर सशस्त्र संघर्ष का जोश, यहाँ तक कि जीवन सहित सब कुछ कुर्बान कर देने की तत्परता और गुरिल्ला संघर्ष के लिए खुद को मिलिट्री ट्रेनिंग से लैस करना ही केवल एक सही क्रान्तिकारी पार्टी नहीं बना देता है।

अगला सवाल सही क्रान्तिकारी सिद्धांत का है। क्रान्तिकारी सिद्धांत से लेनिन का मतलब सिर्फ एक पार्टी के राजनैतिक प्रोग्रामों और नीति से ही नहीं था बल्कि विज्ञान सहित जीवन के तमाम पहलुओं को समेटे हुए ज्ञान की विभिन्न शाखाओं को समझ और तजुबों को द्रष्टात्मक तरीके से समन्वित करते हुए पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा विकसित ज्ञानजगत की सम्पूर्ण परिधि से था। सीपीआई(माओवादी) नेतृत्व मार्क्सवादी दर्शन की ऐसी कोई समग्र समझ लेकर आगे नहीं आया। इस विषय पर इस पार्टी के पास कोई साहित्य नहीं है और न ही इस पहलू पर इसके नेताओं को जनता के बीच कोई सैद्धान्तिक प्रचार करते पाया गया है। दूसरा बिन्दु एक देश की सरजमीन पर मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विज्ञान के उचित प्रयोग और विशेषीकरण के जरिये ठोस स्थिति के ठोस विश्लेषण पर आधारित क्रान्ति के सिद्धांत, स्तर और रणनीति को निर्धारित करने के बारे में है। सीपीआई(माओवादी) के अनुसार, "... भारतीय समाज का चरित्र अर्ध औपनिवेशिक, अर्ध सामंती है। भारतीय क्रान्ति को दो चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहले अर्ध औपनिवेशिक, अर्ध सामंती समाज का एक स्वतंत्र नव जनवादी समाज में परिवर्तन होना चाहिए।" (द स्टेट्समैन दिनांक 7-9-2005 में उद्धृत) यह साफ जाहिर है कि पूर्ववर्ती सीपीआई(एमएल) और नक्सलवादी नेतृत्व की तरह ही सीपीआई(माओवादी) ने भी चीनी मॉडल की अर्धों नकल का रास्ता चुना, भारतीय वास्तविकता पर चीनी परिस्थिति को थोपा और इस तरह भारतीय समाज के ठोस चरित्र और चल रहे वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निर्धारित करने में वे पूरी तरह गलत हैं। एक ठोस परिस्थिति में मार्क्सवादी विज्ञान को ठोस तरीके से लागू करते हुए महान माओ त्से-तुंग ने दिखाया था कि क्रान्तिपूर्व चीन एक स्वतंत्र और लोकातांत्रिक देश नहीं बल्कि अर्ध औपनिवेशिक, अर्ध सामंती देश था जिसमें इस्तेमाल करने के लिए संसद नहीं थी और मजदूर आन्दोलनों को संगठित करने का कानूनी अधिकार भी नहीं था। इसलिए क्रान्ति का काम वहाँ बागावत और युद्ध छेड़ने से पहले कानूनी संघर्षों के एक लम्बे दौर से गुजरना नहीं था और न ही पहले बड़े शहरों पर कब्जा करना और बाद में ग्रामीण क्षेत्र पर कब्जा करना था बल्कि इसके विपरीत था। क्या मौजूदा भारतीय राजसत्ता के ढाँचे से इसका कोई मेल है? बल्कि उल्टे, भारत हर लिहाज से एक अत्यधिक विकसित पूँजीवादी अर्थव्यवस्था है जिसने पहले ही साम्राज्यवादी विशिष्टताएं विकसित कर ली हैं और एकल मिलिट्री-प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मजबूती से कायम पूँजीवादी राजसत्ता है। एक पूँजीवादी देश और एक अर्ध औपनिवेशिक, अर्ध सामंती चीन के बीच फर्क दिखते हुए माओ त्से-तुंग ने चीनी तजुबों के यांत्रिक और जड़सूत्रवादी आरोपण के खिलाफ भी चेलावनी दी थी। आगे स्पष्ट करते हुए उन्हे कहा था, "... दूसरों से सीखने के बारे में दो भिन्न नजरियें हैं। एक, चाहे हमारी परिस्थितियों के अनुकूल हो या न हो, हर चीज को प्रत्यारोपित करने का जड़सूत्रवादी नजरिया... दूसरा नजरिया है अपने दिमाग का इस्तेमाल करना और उन चीजों को सीखना जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल हैं, यानी जो भी तजुबों हमारे लिए उपयोगी हैं उसे आत्मसात करना। यही नजरिया हमें अपनाया चाहिए।" (ऑन द करैक्ट हैण्डलिंग ऑफ कन्ट्राडिक्शन अमंग द पीपुल, पृ. 75) उन्हे इस बात पर भी बार-बार जोर दिया था कि "... सैद्धान्तिक और राजनैतिक लाइन का सही या गलत होना ही हर चीज को तय करता है।" (संकलित रचनाएं, खण्ड पृ. 441) उन्हे व्याख्या की थी कि अगर किसी की मूल राजनैतिक लाइन मतलब शत्रु का निर्धारण गलत है तो तमाम क्रान्तिकारी जुमलों, संघर्षशील मानसिकता और वाञ्छित क्रान्ति के हक में बातें करने के बावजूद उसका पतन अवश्यभावी है। इसके विपरीत, अगर किसी की लाइन सही है तो आने वाले दिनों में निश्चित

(शेष पृष्ठ 6 पर)

कॉमरेड शिवदास घोष

(पृष्ठ 2 का शेष)

था? उसे याद करना है हमें। देश की जनता तक उस संदेश को ले जाना है। उन्होंने कहा था कि देश की जनता की महान कुर्बानियों की बदौलत हमें यह आजादी मिली। आजादी आन्दोलन में काले पानी की सजा किसने भूगी थी? लाठियाँ किसने खायी थी? कुर्बानियाँ किसने दी? साढ़े 19 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़े खुदीराम से लेकर करतार सिंह सराभा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, प्रीतिलता, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष तक ये सभी नौजवान किन घरों के बेटे-बेटियाँ थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और उसका सारा फल हड़प ले गया इस देश का पूंजीपति वर्ग। यही देखकर काँ. घोष बोले थे कि इस खुशी के बावजूद कि इन कुर्बानियों की बदौलत अंग्रेजों को जाना पड़ा, अत्याचारी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के हाथों से निकलकर शासन की बागडोर देशी अत्याचारियों के हाथ में आ गयी। जिस मशीनी पर बैठकर अंग्रेज, अंग्रेज व्यापारी, अंग्रेज पूंजीपति, विदेशी पूंजीपति जिसे हम साम्राज्यवादी कहते हैं, हुकम चलाते थे, भारत की छाती पर बूट रखकर जनता का शोषण करते थे वह शोषण-शासन देशी पूंजीपतियों के हाथों में आ गया। किसी और शख्स ने यह नहीं बताया, एकमात्र काँ. घोष ने ही हमें यह बताया। उन्होंने यह भी बताया कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, ठीक उसी समय हमारे पड़ोसी देश चीन में जहाँ रजवाड़ों का शासन था और कहीं जापानी, कहीं अमेरिकी साम्राज्यवाद का शासन था, वे लोग भी लड़ाई लड़ रहे थे। वहाँ क्रांति हुई और समाजवादी व्यवस्था कायम हुई। पूंजीपतियों को शासन में आने ही नहीं दिया गया। काँ. घोष ने दिखाया कि ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि चीन में किसानों-मजदूरों को सही नेतृत्व मिला। वहाँ सही कम्युनिस्ट पार्टी, सर्वहारा वर्ग की सही क्रांतिकारी पार्टी मौजूद थी। उन्होंने आगे बताया कि भारत की आजादी आंदोलन के अंदर ही भारत की कोई सच्ची कम्युनिस्ट पार्टी होती तो देशी पूंजीपतियों 343त का शासन आना कदापि संभव नहीं होता। आजादी आंदोलन में कांग्रेस थी लेकिन उस पर गाँधी, नेहरू जैसे लोगों का प्रभाव रहा। आखिर तक कांग्रेस पूंजीपतियों की पार्टी बन गई और आज भी है। इसके समझौतावादी नेतृत्व में देश के शासन की बागडोर पूंजीपति वर्ग के हाथ में आयी जिसको आज हम भुगत रहे हैं।

उन्होंने इतिहास से सीखा अंग्रेजों को देश से निकाल देने के बाद आजाद भारत में सबको समान रूप से आजादी का हक, सबको शिक्षा, दवा, इलाज का इंतजाम, रोजगार की गारंटी, जिसे कहते हैं जनता की सच्ची मुक्ति, वह नहीं मिल पायी। उन्होंने चंद मुट्ठी भर साधियों को लेकर एसयूसीआई(सी) का गठन किया और कहा कि 15 अगस्त, 1947 को जो आजादी मिली वह आजादी पूंजीपति वर्ग को मिली। इसे उखाड़ फेंककर समाजवाद कायम करना ही क्रांति का स्वरूप होगा।

क्रांतिकारी बनने के संदर्भ में काँ. घोष ने कहा कि कोई भी क्रांतिकारी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। वह अपने समय की सबसे उन्नत विचारधारा की उपज होता है। स्वयं काँ. घोष जब स्कूल में पढ़ते थे, उस वक्त समाज में जो सबसे उन्नत विचारधारा थी, जो महापुरुष थे उनके विचार की छाप मन मस्तिष्क पर पड़ी। इसलिए वे इतिहास की उपज थे। उनके दिल-दिमाग में एक कसक पैदा हुई कि समाज बदलना चाहिए। उन्होंने शोषित-पीड़ित मजदूर-किसानों को मुक्ति की राह दिखायी। समाज में अच्छा भी है, बुरा भी है। निर्भर करता है कि हम क्या लेते हैं। समाज में अपराध है, नीच कर्म भी है और समाज में उन्नत क्रांतिकारी धारा भी है। हम एक इन्सान का जीवन जीना चाहते हैं। इन्सान का जीवन क्या होता है? जो सर उठाकर जी सके, अन्याय-अत्याचार का प्रतिकार कर सके, वही इन्सान कहलाता है।

मार्क्सवाद को छोड़कर कोई भी दर्शन समाज को मुक्ति का रास्ता नहीं दिखा सका। आज तक दुनिया में जितने दर्शन आये, उनमें मार्क्सवाद सबसे उन्नत दर्शन है। पूंजीपतियों द्वारा मजदूर-किसानों का शोषण किया जा रहा है। लेकिन इससे मुक्ति का उपाय आज राष्ट्रवाद के चिंतन में नहीं है। यह राष्ट्रवाद आज चंद पूंजीपतियों के हाथों में जनता पर अन्याय में मददगार बना हुआ है।

आज पूरा विश्व पूंजीवाद संकट से घिरा हुआ है। बाजार का संकट है। इस संकट से उबरने का रास्ता एशिया, यूरोप, अमेरिका आदि कहीं के पूंजीपतियों के



पटना में स्मृति सभा को संबोधित करते हुए काँ. सत्यवान

पास नहीं है। पूंजीवाद जब आया था तब स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा दिया था। इसने अनेक वैज्ञानिक और साहित्यकार पैदा किये थे। आज मरणसन्न पूंजीवाद कुछ भी अच्छा नहीं दे सकता। रूस में लेनिन के नेतृत्व में पूंजीवाद को उखाड़ फेंककर समाजवाद कायम किया गया था। हमारे देश के महान कवि, महापुरुष रवीन्द्रनाथ ठाकुर सोवियत रूस जाकर जब वापस लौटे तो किसी ने उनसे पूछा कि आप रूस में क्या देखकर आए? उन्होंने कहा कि अगर मैं रूस नहीं जाता तो मेरा जीवन बेकार हो जाता। मैं तीर्थ होकर आया हूँ। रूस ईमानदारी का मंदिर है। वहाँ लोभ को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने समाजवाद की भूरी-भूरी प्रशंसा की।

आज अमेरिका में आवाज उठ रही है कि 'हम 99 फीसदी पर 1 फीसदी का राज नहीं चलेगा।' 'वालस्ट्रीट पर कब्जा करो।' दुनिया में शोषण के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। भूमंडलीकरण यह नारा देकर आया था कि देश तरक्की करेगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। आज अमेरिका जो दुनिया को तहस-नहस करने की ताकत रखता है वह सबसे बड़ा कर्जदार है। काँ. घोष ने दिखाया कि क्रांति के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए व्यक्तिवाद को छोड़ना होगा, निजी स्वार्थ को छोड़कर सामूहिक स्वार्थ को अपनाना होगा। निजी समझदारी को क्रांतिकारी समझदारी में बदलना होगा। जिस प्रकार काँ. घोष ने क्रांति की जिम्मेवारी अपने कंधे पर ली, उसी

शहीद खुदीराम बोस को याद किया

पिलानी (राजस्थान) : यहाँ शहीद खुदीराम बोस का शहीदी दिवस-11 अगस्त एआईडीएसओ के तत्वावधान में मनाया गया। डॉ. रवीकांत पाण्डेय, काँ. विष्णु, दीपक दहिया, राजन्द्र सिहाग ने सभा को संबोधित किया। शहीद को श्रद्धांजली देते हुए मुख्य वक्ता एआईडीवाईओ के काँ. शंकर दहिया ने क्रांतिकारी शहीद के जीवन-संघर्ष से प्रेरणा लेकर वर्तमान में अपने फर्ज को निभाने के लिए आगे आने का छत्र-नौजवानों से आह्वान किया।

अनुबंध आधारित स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मेलन



दिल्ली में 30 जुलाई को आशा किरण होम कॅम्प्लेक्स, रोहिणी में दिल्ली गवर्नमेंट केंद्रकच्युअल हेल्थ इम्प्लाइज यूनियन का पहला वार्षिक सम्मेलन सम्पन्न हुआ। सम्मेलन को युनियन के अध्यक्ष बी.एस. दहिया और एआईयूटीयूसी के काँ. हरीश त्यागी ने संबोधित किया।



15 अगस्त को ए.आई.एम.एस.एस. द्वारा दिल्ली के नार्थ एवेन्यू में आयोजित चित्रकला, गायन व खेलकूद प्रतियोगिता के पुस्तकार वितरण समारोह में सभा को सम्बोधित करते हुए संगठन की दिल्ली राज्य सचिव श्रीमती रितु कौशिक, समारोह का मंच संचालन श्रीमती संध्या ने किया।



प्रकार हमें भी लेनी होगी। यह काम हम कर सकते हैं तभी सही मायने में काँ. घोष के प्रति सच्ची श्रद्धांजली होगी। इसके लिए संघर्ष करना होगा। इंकलाब जिन्दाबाद! कॉमरेड शिवदास घोष लाल सलाम!!

उत्तराखण्ड

रूद्रप्रयाग : उत्तराखण्ड के रूद्रप्रयाग में नए बस अड्डे के पास चल रहे राहत शिविर कार्यालय में सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष का स्मृति दिवस 5 अगस्त को स्मृति सभा करके मनाया गया। सभा की अध्यक्षता एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) गुजरात राज्य कमेटी सदस्य काँ. तपन दासगुप्ता ने की। सभा के मुख्य वक्ता पार्टी के दिल्ली राज्य सचिव काँ. प्रताप सामल थे। सभा में राहत कार्यों में जुटे मैडिकल सर्विस सेक्टर और पार्टी के वालंटियरों के अलावा स्थानीय लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम में उत्तराखण्ड आपदा व पुनर्वासन जन समिति के संयोजक काँ. मुकेश सेमवाल भी उपस्थित थे।

मुरादाबाद (उ.प्र.) में तीर्थंकर महावीर वि.वि. की एमबीबीएस की छात्रा नीरज भड़ाना के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग पर 30 जुलाई को एआईडीवाईओ, एआईएमएसएस और एआईयूटीयूसी की ओर से प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा



ज्वलंत शैक्षणिक समस्याओं पर परिचर्चा

सागर (म.प्र.) : ऑल इण्डिया सेव एज्युकेशन कमेटी, सागर ने शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण और मानवीय मूल्यों के ह्रास आदि "ज्वलंत शैक्षणिक समस्याओं" को लेकर आदर्श संगीत महाविद्यालय में 4 अगस्त को एक परिचर्चा का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता कमेटी के राज्य सचिव डॉ. रामावतार शर्मा ने की। इसमें केन्द्रीय वि. वि. के प्रो. ओ.पी. श्रीवास्तव मुख्य अतिथि थे। केन्द्रीय वि. वि. के हिन्दी विभाग से डॉ. आशुतोष मिश्रा, मानवशास्त्र विभाग वि.वि. सागर से डॉ. राजेश गौतम और डॉ. आलोक के अलावा, पी.आर. मलैया, अधिवक्ता भारत पटेल, जगमोहन सिंह लौधी, ललित मिश्रा और डॉ. कुसुम सुरभि ने भी अपने विचार व्यक्त किये। राकेश पटेल द्वारा गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता अशोक कुशवाहा ने किया।



व्यक्तिगत हत्याएं और क्रांतिकारी राजनीति ..

(पृष्ठ 4 का शेष)

ही राजनैतिक सत्ता हासिल करेगा और सफलतापूर्वक क्रान्ति का नेतृत्व करेगा।

व्यक्तिगत हत्याएं और व्यक्तिगत आतंक

जाहिर है कि सीपीआई(माओवादी) नेतृत्व किसी ने किसी तरह उन्हीं गलतियों को दोहराने और उन्हीं परिणामों को न्यौता देने के लिए कटिबद्ध है। त्रुटिपूर्ण सैद्धान्तिक सूत्रीकरण के अलावा, यह पार्टी “ ‘वर्ग शत्रु का खात्मा करने’ में और सांगठनिक लक्ष्यों को हासिल करने के तरीकों के तौर पर उग्र हिंसा में” अपने यकीन को बार-बार दोहरा रही है। (साउथ एशिया टेरिज्म पोर्टल) जैसा कि लगता है सीपीआई(माओवादी) इस तर्क से सहमत है कि आतंकवादी कार्रवाइयाँ पूँजीवादी स्टेट मशीन को कमजोर करती हैं और इसलिए क्रांतिकारी प्रक्रिया में सहायक होती हैं। लिहाजा ‘मास लाइन’ का अनुसरण करने के नाम पर अपनी फील्ड कार्रवाइयों और व्यक्तिगत हिंसा और आतंक छेड़ने की ‘स्क्वेड कार्रवाइयों’ पर यह जोर देती है। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि त्रुटिपूर्ण सैद्धान्तिक-राजनैतिक नजरियों के तहत 1960 के दशक में नक्सलवादी नेताओं द्वारा यह ऐलान किया गया था कि “तमाम वर्ग और जन संगठन संशोधनवाद के राजमार्ग हैं”। जाहिर है कि इसका अनुमोदन सीपीआई(माओवादी) द्वारा भी किया गया है। इसलिए उनके अनुसार एक दमनात्मक राजसत्ता का एकमात्र संभावित जवाब स्वतःसिद्ध रूप से सशस्त्र संघर्ष ही हो सकता है और दिये गये संदर्भ में ऐसे सशस्त्र संघर्षों का मतलब है घात लगा कर हमले करना, व्यक्तिगत हत्याएं करना और चुनिंदा पाकेटों में आतंक का बोलबाला कर देना। उनका मानना है कि यह राजनीति स्वतःस्फूर्त ढंग से एक राजनैतिक आन्दोलन और एक राजनैतिक क्रांति को भी प्रेरित करेगी। किसी को भी ऐसे विचारों के पीछे के सैद्धान्तिक गड़बड़झाले को समझना होगा। शासक पूँजीपति वर्ग को समग्र तौर पर शत्रु के रूप में देखने की बजाय पूर्ववर्ती नक्सलवादियों की तरह ही सीपीआई(माओवादी) नेतृत्व भी चंद एक व्यक्तियों को ‘वर्ग’ शत्रुओं के रूप में चिन्हित करते हैं और उन्हें खत्म कर देने की योजना बनाते हैं। विडिन्न रूप से व्यक्तिगत पुलिस वालों, बुर्जुआ राजनैतिक नेताओं, भूमिामियों या अफसरशाही के सदस्यों की सरासर हत्याओं की यह लाइन व्यवस्था को न तो बदलेगी और न ही बदल सकती है। उल्टे यह पूँजीवाद को ही बचायेगी। सर्वहारा क्रांतिकारियों को राजनैतिक फायदा उठाने के लिए लोगों को आतंकित करने या क्रांतिकारी राजनीति में शामिल कराने के लिए उग्राने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो सर्वहारा वर्ग चेतना से लैस हैं उनके लिए पूँजीपति वर्ग के खिलाफ संघर्ष निरव्यक्तिक है और एक वर्ग संघर्ष है। उनकी नफरत वर्ग के खिलाफ है न कि व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के खिलाफ। दीर्घस्थायी कष्टसाध्य वैचारिक-सैद्धान्तिक संघर्ष और वर्ग संघर्ष व जन संघर्ष को तीव्रतर करने के जरिये वे धीरे-धीरे लोगों को क्रांति के लिए तैयार करते हैं। इसके लिए कोई शोर्ट कट नहीं है। इसके विपरीत सीपीआई(माओवादी) नेतृत्व के नजरिये से स्वतःस्फूर्तता के सिद्धांत की बू आती है। वे लोगों को बुर्जुआ व्यवस्था के रक्षकों के चंगुल से मुक्त कराने के दीर्घस्थायी सैद्धान्तिक संघर्ष की जरूरत को नकारने के साथ-साथ दीर्घस्थायी वर्ग संघर्ष और जनसंघर्षों की जरूरत को भी नकारते हैं।

इस संबंध में महान मार्क्सवादी अंधोरिंटियों की शिक्षाओं को याद करना बहुत जरूरी है। 1880 में एक पत्र में मार्क्स ने एंगेल्स को लिखा था, “आतंक का बोलबाला। इसे हम उन लोगों के बोलबाले के रूप में समझते हैं जो आतंक को प्रेरित करते हैं; इसके विपरीत यह उन लोगों का बोलबाला है जो खुद भयभीत हैं। आतंक ज्यादातर फिजूल के जुल्मों का समावेश है जिसे खुद को आश्वस्त करने की खातिर डरे हुए लोगों द्वारा अंजाम दिया जाता है।” लेनिन के अनुसार आतंकवाद ‘जनआन्दोलन को समझने में नितान्त असफलता और इसमें विश्वास की कमी’ को प्रतिबिम्बित करता है। 1880 के दशक में जारशाही रूस में नरोदिकों के रूप में जाने जाने वाले एक ग्रुप ने किसानों और मेहनतकश वर्ग के बीच जन क्रांतिकारी काम करना तो छोड़ दिया और जारशाही का मुकाबला करने की पद्धति के तौर पर व्यक्तिगत आतंकवाद के जरिये व्यक्तियों की हत्या करने की नीति को अपनाया था। लेनिन ने उन्हें गहन सैद्धान्तिक संघर्ष के जरिये खूब लताड़ा था और दिखाया था कि कैसे नरोदिकों

ने उस समग्र वर्ग के खिलाफ संघर्ष से मेहनतकश लोगों का ध्यान भटकया था। मजदूर वर्ग और किसान समुदाय की क्रांतिकारी पहलकदमी और गतिविधियों को बाधा पहुँचाई थी और मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी के निर्माण की प्रक्रिया को धीमा किया था। उन्होंने जन उभार के दौरान होने वाले आतंकवाद (जिससे उनका मतलब ‘हिंसा’ से था) और दुस्साहसिक “व्यक्तिगत आतंकवाद” जिससे जन समर्थन हासिल नहीं था, के बीच फर्क को साफ-साफ दिखाया था और कहा था, “रूसी क्रांति का इतिहास दर्शाता है कि एक पार्टी हमेशा व्यक्तिगत आतंक का सहारा लेती है जबकि इसे जनसमर्थन हासिल नहीं होता है।” आगे व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया, “खुल कर सामने आ गया है कि अराजकतावादियों का दर्शन बुर्जुआ दर्शन है। उनके व्यक्तिवादी सिद्धांत और उनके व्यक्तिवादी आदर्श पूरी तरह समाजवाद के विपरीत हैं। उनके विचार बुर्जुआ समाज के भविष्य को अभिव्यक्त नहीं करते हैं जो अदम्य ताकत के साथ श्रम के सामाजीकरण की ओर डग भर रहा है बल्कि वर्तमान और उस समाज के अतीत के भी बिखरे हुए और अलग-थलग पड़े हुए छोटे उत्पादकों पर आधिपत्य के अनिश्चित अवसर को अभिव्यक्त करते हैं।”, “... उनके रणकौशल (यानी अराजकतावादियों के-सम्पादक). ..राजनैतिक संघर्ष का परित्याग कर देने, सर्वहाराओं को बांट देने और असल में उनको एक या दूसरी बुर्जुआ नीति में निष्क्रिय भागीदारों में तब्दील कर देने के बराबर है।” (सोशलिज्म एण्ड एनार्किज्म, कलैक्टिव वर्क्स, खण्ड 10 पृ. 73) उन्होंने यह भी कहा था, “आतंकवाद के लिए वरीएता इस तथ्य से बड़ी गहराई से जुड़ी हुई है कि बिल्कुल शुरुआत से ही मजदूर वर्गीय आन्दोलन से खुद को अलग-थलग रखा और अभी भी रख रहे हैं क्रांतिकारी वर्ग जो वर्ग संघर्ष छोड़ रहा है उसके साथ हिस्सेदार बनने का कोई भी प्रयास किये बिना” (रिवोल्यूशनरी एडवेंचरिज्म, कलैक्टिव वर्क्स, खण्ड 6 पृ. 189) इसलिए “आतंकवादी कार्यों के लिए आह्वान करना...केवल उस बेहद जरूरी जिम्मेदारी को टालने के ढंग हैं जो आज रूसी क्रांतिकारियों के कंधों पर आ पड़ी है, यानी सर्वांगीण राजनैतिक आन्दोलन को संगठित करना।” (क्या करें, संकलित रचनाएं, खण्ड 1, भाग 1, पृ. 250) उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि “हमें मजदूरों को यह समझाने की जरूरत है कि जहाँ निस्संदेह कभी-कभी जासूसों, उतेजना फैलाने वाले एजेण्टों और देशद्रोहियों को मारना अत्यंत अपरिहार्य हो जाता है वहीं इसको एक सिस्टम बना देना पूरी तरह अवांछित और गलत है।” (फुटनोट : लैटर टू ए कॉमरेड ऑन आवर ऑर्गेनाइजेशनल टाक्स, कलैक्टिव वर्क्स, खण्ड 6; पृ. 245) और उन्होंने इसे पूरी तरह साफ कर दिया कि “बोलशेविज्म वर्षों तक निम्न-पूँजीवादी क्रांतिवाद के खिलाफ लड़ कर बढ़ा, पनपा और मजबूत हुआ है। इस निम्न-पूँजीवादी क्रांतिवाद में अराजकतावाद की कुछ बू आती है, या यूँ कहिये कि उसने कुछ बारात अराजकतावाद से उधार ली है और वह सुसंगत सर्वहारा वर्ग संघर्ष के लिए आवश्यक बुनियादी बातों और परिस्थितियों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।” (“वामपंथी” कम्प्युनिज्म-एक बचकाना मर्ज, संकलित रचनाएं, खण्ड 3, भाग 1; पृ. 442)। आगे व्याख्या करते हुए स्टालिन ने दिखाया कि “बिन्दु यह है कि मार्क्सवाद और अराजकतावाद पूर्णतः भिन्न सिद्धांतों पर निर्मित हुए हैं... अराजकतावादी सिद्धांत के अनुसार जब तक व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक जनता की मुक्ति असम्भव है। तदनुसार, इसका नारा है: ‘हर चीज व्यक्ति के लिए है।’ वहीं मार्क्सवाद का मूलाधार जनता है, इसके मतानुसार जनता की मुक्ति व्यक्ति की मुक्ति के लिए पूर्वशर्त है। कहने का आशय है मार्क्सवाद का मानना है कि व्यक्ति की मुक्ति तब तक असम्भव है जब तक कि जनता मुक्त नहीं हो जाती। तदनुसार, इसका नारा है: ‘हर चीज जनता के लिए।’ (एनार्किज्म या सोशलिज्म?, कलैक्टिव वर्क्स, खण्ड 1 पृ. 299)। इस तरह लेनिन-स्टालिन ने व्यक्तिगत आतंक व व्यक्तिगत अराजकतावाद का खण्डन किया है और दिखाया है कि कैसे ये मार्क्सवाद के अति मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ हैं।

लेनिन और स्टालिन की तरह, माओ त्से-तुंग ने भी वर्ग संघर्ष के नाम पर आतंकवाद में फिसल जाने के खिलाफ चेतावनी देते हुए आगाह किया था। यह भी कहा जा सकता है कि कहीं जापान-विरोधी आक्रामक युद्ध को “विध्वंसक युद्ध” के रूप में उनकी व्याख्या को किसी के द्वारा गलत न समझ लिया जाए, इसलिए उन्होंने इसे स्पष्ट किया कि चीन

की तत्कालीन खास परिस्थितियों में “...मुहिमों में विनाश की लड़ाइयाँ रणनीतिक घिसाव-थकाव के उद्देश्य को हासिल करने का साधन हैं। इस मायने में विनाश की लड़ाई भी घिसाव-थकाव की लड़ाई ही है। विनाश के जरिये घिसाव-थकाव को मुख्य साधन बना कर ही चीन अपने दीर्घकालीन युद्ध को चला सकता है।” (दीर्घकालीन युद्ध के बारे में, संकलित रचनाएं, खण्ड 2; पृ. 309) यहाँ दुश्मन की भाड़े की फौज का विध्वंस किया गया, इक्का-दुक्का व्यक्तियों का नहीं। क्रांतिकारी संघर्ष संचालित करने के नाम पर स्वधोषित माओवादी अपने नक्सलवादी पूर्ववर्तियों की तरह व्यक्तिगत हत्या और आक्रामक हिंसा को अंजाम देने का सहारा लेते हुए माओ त्से-तुंग के एक उद्धरण का हवाला देते हैं कि “राजनैतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है” और इसे व्यक्तिगत हत्या और आतंक को अंजाम देने की अपनी कार्रवाई को जायज ठहराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करके वे कभी नहीं सोचते कि उनके ऐसे मंतव्य न केवल क्रांतिकारी राजनीति के बारे में गलत समझदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि प्रतिक्रिया की ताकतों और निहित स्वार्थों को आम तौर पर मार्क्सवाद- लेनिनवाद को और विराट मार्क्सवादी अंधोरिंटि माओ त्से-तुंग जैसे सर्वहारा के महान नेता को भी बदनाम करने का मौका दे रहे हैं, मानो वे व्यक्तिगत आतंक और हत्या के समर्थक और सूत्रपात करने वाले हों। क्रांतिपूर्व चीन के विशेष संदर्भ में माओ ने बताया था कि “...देश में सामंती विभाजन होने की वजह से...जिसके पास ज्यादा बंदूकें होती हैं उसके पास ज्यादा सत्ता है। इन परिस्थितियों के रहते हुए सर्वहारा की पार्टी को स्पष्ट रूप से समस्या की जड़ को पहचान लेना चाहिए।” इसलिए “...सशस्त्र संघर्ष के बिना चीन में सर्वहारा वर्ग और कम्प्युनिस्ट पार्टी न तो अपने लिए कोई स्थान ही बना सकेंगे, और न ही वे किसी क्रांतिकारी काम को ही पूरा कर सकेंगे।” (संकलित रचनाएं, खण्ड 2; पृ. 393, 390-91) लेकिन ऐसा एक वक्तव्य क्या इस बात को नकारता है कि सही विचारधारा से लैस लोग ही क्रांतिकारी संग्राम में सबसे शक्तिशाली बंदूक होते हैं? माओ ने खुद ही स्पष्टीकरण दिया है, “...‘हथियार ही सब कुछ तय करते हैं’ का तथाकथित सिद्धांत...एक यांत्रिक नजरिया है...युद्ध में हथियार महत्वपूर्ण तत्व अवश्य होते हैं लेकिन निर्णायक तत्व नहीं; निर्णायक तत्व मनुष्य ही होता है, वस्तुएं नहीं। ताकतों के बीच का यह मुकाबला न केवल दोनों पक्षों की फौजी और आर्थिक ताकत के बीच का मुकाबला है, बल्कि इंसानी ताकत और मनोबल के बीच का मुकाबला भी है।” (दीर्घकालीन युद्ध के बारे में, संकलित रचनाएं, खण्ड 2; पृ. 243-244)

समयपूर्व क्रांतिकारी विद्रोह का आह्वान

दूसरा उल्लेखनीय पहलू है क्रांतिकारी विद्रोह के लिए आह्वान करने का समय। जैसा कि हमने ऊपर दिखाया है क्रांति केवल तभी हो सकती है जब भावगत और वस्तुगत दोनों परिस्थितियों परिपक्व हों। इससे पहले क्रांति का आह्वान दुर्भाग्य को न्यौता देने के समान है और जनता जो अभी तैयार नहीं हुई है उसे प्रतिक्रिया के भेड़िये के सामने फेंक देना है। इसी वजह से लेनिन ने कहा था, “अगुआ दस्ते के बल पर ही जीत हासिल नहीं की जा सकती है। समूचे वर्ग से पहले, व्यापक जनता द्वारा या तो अगुआ दस्ते के सिधे समर्थन या कम से कम इसके प्रति हितकारी तटस्थ की स्थिति ग्रहण करने से पहले और ऐसी एक स्थिति जिसमें वे संभवतः दुश्मन का समर्थन नहीं करेंगे, निर्णायक युद्ध में अकेले अगुआ दस्ते को झोंक देना केवल मूर्खता ही नहीं बल्कि एक अपराध होगा। इसके लिए जनता को अपना खुद का राजनैतिक तजुर्बा होना चाहिए।” (“वामपंथी” कम्प्युनिज्म-एक बचकाना मर्ज, कलैक्टिव वर्क्स, खण्ड 10) माओ त्से-तुंग ने भी बताया था कि एक क्रांति केवल इसी वजह से नहीं होती है कि पार्टी ने इसे करने का फैसला लिया है। इसलिए उन्होंने चेतावनी दी थी : “कुछ कॉमरेड भावगत और वस्तुगत परिस्थितियों की अवहेलना करते हुए क्रांतिकारी उतावलेपन की व्याधि का शिकार हैं। वे जनता के बीच छोटे-छोटे और व्यौरवार काम करने की जहमत नहीं उठाएंगे बल्कि खामखाली का शिकार बने हुए केवल बड़ी-बड़ी चीजें करना चाहते हैं। यह पुस्तुचिन्म (विद्रोहवाद) का अवशेष है। यानी जनता के एक छोटे हिस्से पर भरोसा करना और स्थानीय विद्रोहों के सिलसिले का प्रयास करना है।” (संकलित रचनाएं, खण्ड 2 पृ. 107)। इस बात को और भी स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था, “जब जनता अभी तक जागरूक नहीं हुई है, ऐसे

व्यक्तिगत हत्याएं और क्रांतिकारी राजनीति

(पृष्ठ 6 का शेष)

में अगर हम आक्रमण करने का प्रयास करें तो यह दुस्साहस होगा। अगर जनता को ऐसा कुछ करने के लिए कहते हैं जो उसकी इच्छा के विरुद्ध है तो निश्चित ही हम असफल होंगे। अगर हम उस समय आगे नहीं बढ़ते हैं जब जनता आगे बढ़ने की माँग कर रही है तो यह दक्षिणपंथी अवसरवाद होगा।” (ए टाक टू द एडिटोरियल स्टाफ ऑफ द सांसी-सुइयून डेली, संकलित रचनाएं, खण्ड 2 पृ. 243) उन्होंने यह भी सीख दी, “अगर मनुष्य अपने काम में सफल होना चाहता है, अर्थात् प्रत्याशित परिणाम प्राप्त करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह अपने विचारों को वस्तुगत बाहरी जगत के नियमों के अनुरूप बनाये; अगर उसके विचार इन नियमों के अनुरूप नहीं बनेंगे, तो वह अपने व्यवहार में असफल हो जाएगा। जब वह असफल हो जाता है, तो अपनी असफलता से सबक सीखता है, अपने विचारों को सुधार कर बाहरी जगत के नियमों के अनुरूप बना लेता है तथा इस प्रकार अपनी असफलता को सफलता में बदल सकता है।” (व्यवहार के बारे में, संकलित रचनाएं, खण्ड 1 पृ. 530-31) एसयूसीआई(सी) के संस्थापक महासचिव, एक अग्रगण्य मार्क्सवादी चिन्तनकार और मार्क्स-एंगेल्स-लेनिन-स्टालिन-माओ त्से-तुंग के सुयोग्य धारावाहक कॉमरेड शिवदास घोष ने नक्सलवादियों की सैद्धांतिक त्रुटियों को इंगित करते हुए बताया था, “क्रान्ति के नाम पर आजकल नक्सलवादी असल में जिस बात पर अमल कर रहे हैं... और...इसे माओ त्से-तुंग विचारधारा के रूप में पेश करने का प्रयास कर रहे हैं...सारांश में, दरअसल वे कष्टसाध्य सैद्धांतिक-राजनैतिक संघर्षों को संचालित करने की अपरिहार्य जरूरत को नकार रहे हैं... और मानते हैं कि अगर क्रांतिकारी...छिट-पुट व्यक्तिगत आतंकवाद में लिप्त रहें तो यह जनता को क्रांति की ओर आकर्षित करेगा और क्रांतिकारी संगठन अपने आप विकसित हो जाएंगे।...लेकिन इनका माओ त्से-तुंग और उनके विचारों से कोई सरोकार नहीं है। बल्कि वे तथाकथित सिद्धांत मार्क्सवाद-लेनिनवाद और माओ त्से-तुंग विचारधारा के पूरी तरह विपरीत हैं... माओ के नाम पर ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने के जरिये हालांकि माओ की शिक्षाओं से जिनका कोई वास्ता नहीं है, वे राजनैतिक तौर पर अचेत और अनभिज्ञ जनता की नजरों में माओ त्से-तुंग जैसे महान नेता की इज्जत-कद्र भी गिरा रहे हैं।” (कलैक्टिव वर्क्स, खण्ड 2; पृ. 246-47) दुर्भाग्यवश, पूर्ववर्ती नक्सलवादी नेताओं की तरह सीपीआई(माओवादी) का मौजूदा नेतृत्व भी इन बहुमूल्य शिक्षाओं को आत्मसात करने का कोई आसार नहीं दिखा रहा है बल्कि व्यक्तिगत हत्याओं और आतंक फैलाने के अपने एजेण्डे को लागू करता जा रहा है।

परिणाम अनिष्टसूचक है

परिणाम बहुत ही अनिष्टसूचक है अन्तिम विश्लेषण में एक तरफ संकीर्णतावादी-साम्प्रदायिक-अलगाववादी ताकतें जो या तो बुर्जुआ ताकतें हैं या बुर्जुआ वर्ग स्वार्थ की हितसाधक ताकतें हैं, लोगों को डरा रही हैं, मेहनतकश जनता के विभिन्न तबकों के बीच सामंजस्य को गड़बड़ा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सीपीआई(माओवादी) नेतृत्व विच्छिन्न हिंसा, प्लांटिड धमाकों और व्यक्तिगत हत्याओं के जरिये, चाहे उनकी ऐसी मंशा न भी हो, लेकिन मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्से-तुंग विचारधारा से लोगों को दूर धकेल रहा है। इस तरह, वर्ग दुश्मनों के प्रयासों के साथ-साथ माओ त्से-तुंग के तथाकथित अनुयायियों द्वारा लागू की जा रही पूरी तरह गलत लाइन का परिणाम क्रांति के उद्देश्य और उत्पीड़ित लोगों की मुक्ति के रास्ते के लिए समान रूप से घातक है क्योंकि उनके क्रियाकलाप लोगों को राजनीति का विरोधी बना रहे हैं और जनवादी आन्दोलन के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं। ऐसी आतंकी कार्रवाइयों और निर्विचार हिंसा मार्क्सवाद-लेनिनवाद को बदनाम करने के अलावा दमनात्मक पूँजीवादी शासकों को अधिक शक्तों के साथ, अधिक काले कानूनों को लागू करने के जरिये अपने दमनात्मक राज्यंत्र को मजबूत बनाने का बहाना भी दे देता है और हिंसा का मुकाबला करने, आतंकवादियों को हूँद निकालने और राष्ट्र-विरोधी ताकतों, विघटनकारी प्रवृत्तियों, अलगाववादी व विच्छिन्नतावादी कदमों पर लगाय लाने के नाम पर बदतरीन किस्म का राजकीय आतंकवाद लोगों पर बरपाया जा रहा है। इस सब के फलस्वरूप बहुत से मौकों पर डरे हुए और

ध्रमिंत लोग राजसत्ता और सरकार की ऐसी तमाम जनवाद-विरोधी स्वेच्छाचारिता के अनुमोदक बन जाते हैं, यह सोच कर कि इससे उनके जीवन में सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी और आतंक व अराजकता के राज का अंत हो जाएगा। अगर ऐसे बहाने बनाने का मौका नहीं दिया गया होता तो बुर्जुआ राजसत्ता और सरकार द्वारा उठाये गए इन कदमों और आतंकवाद-विरोधी इस तथाकथित मुहिम के खिलाफ मेहनतकश लोगों का भयंकर विरोध खड़ा हो गया होता। इस संदर्भ में सीपीआई(माओवादी) नेतागण, चाहे उनकी मंशाएं कितनी भी अच्छी क्यों न हों, लेकिन क्रांति की सही विचारधारा व पद्धति के बारे में उनकी अज्ञानता की वजह से वे इस तथ्य को ही छिपाने का काम कर रहे हैं कि यह पूँजीवादी राजसत्ता है और शासक पूँजीवाद ही तमाम बुराइयों की जड़ है, इस तरह वे बुर्जुआ वर्ग स्वार्थ की ही पूर्ति कर रहे हैं और शासक वर्ग को कम्यूनिज्म के खिलाफ कुत्सित अभियान चलाने और लेनिन, स्टालिन, माओ जैसी महान मार्क्सवादी अंधोरिष्टियों को बदनाम करने, उन पर व्यंग्यिक्रि करने का भी मौका दे रहे हैं।

दूसरे, जो अत्यंत दुःखद बात है कि राजनैतिक चेतना के अभाव की वजह से बहुत से युवक-युवतियाँ उन्मत्त विद्वेष में अंधे होकर अलगाववादी-साम्प्रदायिक-संकीर्णतावादी और ऐसी ही अन्य विभाजनकारी शक्तियों के पीछे जुट गये हैं, अपने लड़ाकू जन्मे और हिम्मत को दूसरे समुदायों के अपने खुद के ही भाइयों पर गोलियों की बौछार करने में बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ कर दुःखदायी बात यह है कि अत्याधुनिक फौज के साथ दुस्साहसिक मुकाबलों में हजारों की संख्या में वे मारे जा रहे हैं। इसी तरह, क्रांतिकारिता, और शूरवीरता का जाहिरा जोश उभरते हुए और जीवत हजारों छात्र-नौजवानों को नक्सलवादी आन्दोलन के भंवर में खींच लाया था; उन्होंने तहेदिल से व्यवस्था परिवर्तन का सपना देखा था और उज्वल करियर, परम्परागत पारिवारिक सम्बन्धों सहित सब कुछ छोड़ने को तैयार थे और दमनात्मक स्टेट मशीनरी से टकराने में नहीं झिझके थे और अपनी बेशकीमती जान कुर्बान कर दी थी। इसकी पुनरावर्ती सीपीआई(माओवादी) की दुस्साहसिकता में भी हुई है। इस प्रक्रिया में निडर और जांबाज नौजवानों के एक समूह को भी देश अस्मय खो रहा है, जो सही क्रांतिकारी पार्टी के सानिध्य में खुद को क्रांति के उत्साही सेनानियों के रूप में ढाल सकते थे और सही रास्ते पर क्रांति की प्रक्रिया को तीव्रतर कर सकते थे। कितना भारी नुकसान है असल में क्रांतिकारी आन्दोलन का! यही वजह है कि सही मार्क्सवादी-लेनिनवादियों ने व्यक्तिगत आतंकवाद का खण्डन किया है इस बिनाह पर नहीं कि आतंकवाद-दुश्मन के अन्दर दहशत पैदा कर देना-अनैतिक है बल्कि इस वजह से कि व्यक्तिगत आतंकवाद की कार्रवाइयों क्रांति के उद्देश्य को जबरदस्त नुकसान पहुँचाती हैं।

जनवादी आन्दोलन के उभार को यहाँ सबसे बड़ा नुकसान

इसलिए हम देखते हैं कि न्यायसंगत जनवादी आन्दोलन को लहरें पैदा करना समय की माँग है जिसे सही दिशा में और सही क्रांतिकारी नेतृत्व के तहत तीव्रतर करते जाने के क्रम में धीरे-धीरे वर्ग संघर्ष के स्तर तक ऊपर उठाया जाएगा और जैसा कि पहले बताया गया है क्रांति की वस्तुगत व भावगत परिस्थितियों को पूरा करते हुए आखिरकार लोगों की वांछित मुक्ति में पदार्पण करने के लिए पूँजीवाद-विरोधी क्रांति सम्पन्न करने में परिणत हो जाएगा। नकली मार्क्सवादियों सहित वोट-केन्द्रित राजनैतिक पार्टियों द्वारा फैलाया गया संसदीय भ्रमजाल, विभाजनकारिता का घनीभूतीकरण और विभिन्न रंगों की साम्प्रदायिक-संकीर्णतावादी ताकतों द्वारा पैदा किया गया उन्माद और सीपीआई(माओवादी) द्वारा लागू की जा रही व्यक्तिगत हत्या और हिंसा की नीति, क्रांति की इस वस्तुगत प्रक्रिया की राह में जबरदस्त रोड़ा बना रही हैं। अपनी जायज माँगों मनवाने के लिए सचेत जनवादी आन्दोलन के दायरे से बाहर रहने की वजह से जनता की राजनैतिक चेतना का स्तर भी लगातार गिर रहा है, विभिन्न हानिकारक विचारों, विकृत मानसिकता और फासीवादी साजिशों द्वारा अपना शिकंजा सम्पन्न करने में परिणत हो जाएगा। वांछित क्रांतिकारी संघर्ष गठित करने में सहायक न्यायसंगत जनवादी आन्दोलन के रास्त पर खौफजदा लोगों को वापस लाना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। इसके अलावा, शासक वर्ग इस अवसर का लाभ उठा कर उन्हें यह यकीन दिला रहा है कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद उनके हितों के लिए घातक है और चुनावों में हिस्सा लेने के सिवाय उनके पास और

कोई चारा नहीं है। शासक पूँजीपति वर्ग का ताकतवर प्रचारतंत्र लोगों में यह मनोभाव पैदा करने का प्रयास कर रहा है कि राजनीति के तमाम रूपांतर और कुछ नहीं बल्कि अशांति फैलाना, सामान्य स्थिति का भंग करना, कुछ स्वार्थी लोगों, अपराधियों और हिंसा पैदा करने वालों का पेशा है और इसलिए उन्हें इससे दूर रहना चाहिए।

सत्य को आत्मसात करने का लोगों से आह्वान

उत्पीड़ित लोगों को समझना चाहिए कि न तो संसदीयतावाद, न विभाजनकारी मानसिकता का अध समर्थन, न ही बेमतलब हिंसा में लिप्त होना या जिसे माओ त्से-तुंग ने ‘विद्रोहवाद’ कहा है, उन्हें कोई राहत प्रदान कर सकेगा। उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा है वह है तमाम तरह की फूटपरस्ती से ऊपर उठ कर, तमाम गलत धारणाओं से मुक्त होकर, उच्च सर्वहारा संस्कृति व नैतिकता के आधार पर और सही क्रांतिकारी नेतृत्व के तहत सशक्त सतत संगठित जनवादी आन्दोलन गठित करने का रास्ता अपनाना। मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सिवाय और कोई विचारधारा या रीति-नीति उन्हें रास्ता नहीं दिखा सकती है। न तो मार्क्सवाद का मुखौटा लगाये हुए वोट बटोरू सोशल डेमोक्रेट और न ही ‘माओवादी’ बताने वाले गुमराह दिशाहीन अल्ट्रा-एडवेंचरिस्ट मार्क्सवाद-लेनिनवाद को सही क्रांतिकारी लाइन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ से लेकर शिवदास घोष तक-हर किसी ने इन दोनों तरह के भटकवालों और ऐसी विपथित लाइनों के प्रारूपों के बारे में आगाह किया था। इसी तरह, बदतर किस्म के भ्रातृघाती संघर्षों और साम्प्रदायिक व व्यक्तिगत हत्याओं को भडकाने वाले अलगाववादी-साम्प्रदायिक-संकीर्णतावादी आन्दोलनों को जनवादी आन्दोलन समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोगों के आन्दोलन ऐसी ताकतों के चंगुल में फंस कर दिशाहीन न हो जाएँ और विफल न हो जाएँ। जीवन की ज्वलंत माँगों पर जनवादी आन्दोलन की झड़ी के साथ ही साथ लगातार सैद्धांतिक प्रचार के जरिये घोर साम्प्रदायिक और अन्य अलगाववादी-अंधराष्ट्रवादी-संकीर्णतावादी-विच्छिन्नतावादी ताकतों को करारी शिकस्त देनी है। इस तरह की प्रक्रिया में, वोट आधारित नकली मार्क्सवादियों को जनता से अलग-थलग कर देना है और सीपीआई(माओवादी) की गलत मूल राजनैतिक लाइन का पर्दाफाश कर देना है। कॉमरेड शिवदास घोष के कुछ ऐतिहासिक कथनों के साथ हम इस लेख को समाप्त करते हैं : “हालांकि बाहर से देखने पर ऐसा लगेगा कि राजनीति में बहुत सी विरोधी ताकतें हैं लेकिन अंतिम संघर्ष के संदर्भ में स्थिति को देखते हुए, मेरा मानना है कि राजनीति में केवल दो ही परस्पर-विरोधी ताकतें हैं-एक क्रांति की खातिर, दूसरी क्रांति के विरोध में-चाहे किसी भी नाम से उन्हें पुकारा जाए। एक है क्रांति का विरोध करने की राजनीति...दूसरी है क्रांति संगठित करने की राजनीति।” (संकलित रचनाएं खण्ड 3, पृ. 532-33, अंग्रेजी), “क्रान्ति के उच्च प्रतीक लाल झण्डे और कम्यूनिस्ट विचारधारा की सर्वश्रेष्ठता को बुलंद रखने और हमारे देश की पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए...एसयूसीआई(सी) एक लम्बे कष्टसाध्य संघर्ष के जरिये एक कम्यूनिस्ट पार्टी की तमाम विशेषताएं लिए हुए विकसित हुई है।” (संकलित रचनाएं, खण्ड 2; पृ. 278, अंग्रेजी) “आज के समाज में मजदूर-किसानों, शोषित-पीड़ित जनता के विश्वोभ के आधार पर क्रांति बार बार उभरना चाहेगी, लहरों पर लहर की तरह आती दिखाई पड़ेगी। समाज के अन्दरूनी द्वंद्व बार-बार क्रांतिकारी उफान पैदा कर वर्तमान व्यवस्था को आमूलचूल बदल डालने के लिए ललकारेंगे और हरेक आदमी के जमीर को झकझोरते हुए उनसे बार-बार माँग करेंगे कि इन्कलाब होना चाहिए, क्रांति की बहुत जरूरत है लेकिन क्रांति तब तक नहीं होगी, वह बार-बार वापस लौट जाएगी, गुमराह होकर भटक जाएगी, उससे बार-बार प्रतिक्रियावादी फायदा उठा लेंगे जब तक कि क्रांति का नेतृत्व करने लायक क्षमता सहित मजदूर वर्ग की शक्तिशाली क्रांतिकारी पार्टी का आविर्भाव न हो।” (संकलित रचनाएं खण्ड 3, पृ. 390-91, अंग्रेजी) उनकी इस उदात्त अपील पर सकरात्मक प्रतिक्रिया देने, एसयूसीआई(सी) के परचम को बुलन्द करने, वर्ग संघर्ष और जनसंघर्ष को और भी तेज करने और भारतीय क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने का हम सभी से आह्वान करते हैं।



मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न

राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ धरना



श्रमिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए एआईयूटीयूसी की ओर से कॉमरेड सत्यवान

नई दिल्ली : यहां मावलंकर हाल में 6 अगस्त को एआईयूटीयूसी, एटक, इटक, बीएमएस, सीटू, एचएमएस सहित 11 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ। सम्मेलन को एआईयूटीयूसी की ओर से राष्ट्रीय सचिव मण्डल सदस्य कॉमरेड सत्यवान के अलावा बीएन राय(बीएमएस), केके नायर(इटक), तपन सेन(सीटू), गुरुदास दासगुप्ता(एटक), एचएस सिधु(एचएमएस), राजीव डिमरी(एकटू), लता बेन(सेवा), एसपी तिवारी(टीयूसीसी), अशोक घोष(यूटीयूसी) व पेचीमुथु(एलपीएफ) ने भी सम्बोधित किया। कर्मचारी फेडरेशनों के भी नेताओं ने भी इसमें शिरकत की। एआईयूटीयूसी के कॉ. आर के शर्मा अध्यक्ष मण्डल के सदस्य थे।

सम्मेलन में घोषणापत्र सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसमें न्यूनतम वेतन कम से कम 10 हजार रु.

करने, सभी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, पूरी मेहनतकश जनता को सुनिश्चित पेन्शन देने, ठेका मजदूरों को समान काम के लिए नियमित कामगारों के बराबर वेतन व हितलाभ देने, श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने, महंगाई पर रोक लगाने व रोजगार पैदा करने के लिए ठोस कदम उठाने, केन्द्र व राज्य सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में विनिवेश बंद करने, बोनस, भविष्य निधि की अदायगी व पात्रता पर से सभी सीलिंग हटाने, ग्रेज्युटी की मात्रा बढ़ाने, 45 दिन के अन्दर ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने आदि 10 सूत्री मांगों को लेकर आन्दोलन तेज करने का आह्वान किया गया।

25 सितम्बर को सभी राज्यों की राजधानियों में राज्य स्तरीय प्रदर्शन/रैलियां/सत्याग्रह करने और 12 दिसम्बर को संसद पर विशाल प्रदर्शन के साथ-साथ देश भर में जिला मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन करने की घोषणा की गई।

पटना : नगर निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स सहित अन्य टैक्सों में की गयी वृद्धि, मिड डे मिल में व्याप्त भ्रष्टाचार, बस व ऑटो किराये में बेतहाशा वृद्धि, वाडों-मुहल्लों में गंदगी व जलजमाव, स्कूलों-अस्पतालों की बदहाली, भ्रष्टाचार-कदाचार, कमरतोड़ महंगाई तथा राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 13 जुलाई को एसयूसीआई (सी) पटना जिला कमिटी द्वारा शहीद भगत सिंह चौक पर धरना दिया गया।

धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पहले जद(यू)-भाजपा गठबंधन और अब जद(यू) की सरकार ने केन्द्र सरकार की जनविरोधी राह पर चलते हुए विकास के नाम पर राज्य में जिन योजनाओं को लागू किया है, उससे समाज में गैर बराबरी और बढ़ी है। आसमान छूती महंगाई और भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा कहर आम मेहनतकश अवाम को ही झेलना पड़ रहा है। आज मुट्ठीभर अमीर, ठेकेदार, कालाबाजारी, स्टूटबाज, नौकरशाह व सत्ताधारी दलों के नेता मालामाल हो रहे हैं और बहुसंख्यक जनता भयंकर गरीबी व तबाही में जीने को अभिशप्त है। पटना नगर निगम द्वारा मकानों के होल्डिंग टैक्स में दोगुनी, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी द्वारा बिजली दर में करीब 7 फीसद की वृद्धि उठाव व जलापूर्ति की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा, नगर में बस, ऑटो के किराये में भी मनमानी बढ़ोतरी की वक्ताओं ने कड़ी भर्त्सना की। अधिकांश जगहों पर गंदगी का अम्बार लगा होता है। मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए फौगिंग मशीनों द्वारा दवा का छिड़काव नहीं होता है। किसी-किसी मुहल्ले में कई दिनों तक जलजमाव रहता है। पानी जैसी आवश्यक वस्तु की समुचित आपूर्ति करने में भी सरकार सक्षम नहीं है।

उत्तराखण्ड में जन सम्मेलन

श्रीनगर : उत्तराखण्ड में 16-17 जुलाई को आई आपदा से हुई जबर्दस्त तबाही और हजारों यात्रियों व स्थानीय निवासियों की जान-माल के भारी नुकसान के दृश्य टीवी एवं अखबारों द्वारा सब ने देखे हैं। इसमें कितने ही गांव मिट गये। सड़कें और पुल टूट जाने से इस क्षेत्र का सम्पर्क बाकी क्षेत्रों से टूट गया। कितने ही परिवारों के एकमात्र कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से उन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। यहां के जनजीवन, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक स्थिति, शिक्षा व स्वास्थ्य पर आपदा का गहरा असर पड़ा है। आपदा-प्रभावित स्थानीय नागरिक किसी प्रकार अपनी स्थिति को सम्भालने-सुधारने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं।

एसयूसीआई(सी) कार्यकर्ताओं ने पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के आह्वान पर सारे देश से राहत सामग्री एवं आर्थिक सहायता संग्रह करके उत्तराखण्ड के आपदा-प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता केन्द्र शुरू किये। रूद्रप्रयाग में बेस कैम्प और बांसावाड़ा-भीडी में एडवांस कैम्प लगाये। इस कार्य में पूरे देश से 100 से अधिक डॉक्टरों, नर्सों, पैरा मैडिकल स्टाफ और कार्यकर्ताओं ने दुर्गम पहाड़ी रास्तों से पैदल जाकर भी आपदा-प्रभावित 300 गांवों के लगभग साढ़े सात-आठ हजार रोगियों का उपचार किया और दवाइयां दीं। इस आपदा राहत कार्य में स्थानीय नागरिकों का सक्रिय सहयोग मिला। एसयूसीआई(सी) ने पूर्व आपदा राहत कार्यों एवं वर्तमान में उत्तराखण्ड आपदा राहत कार्य के अपने अनुभव से अहसास किया कि आपदा-प्रभावित लोगों का पूर्ण व स्थायी पुनर्वास केवल तभी सम्भव है जब सरकारी तंत्र द्वारा इस ओर पूरा ध्यान दिया जाए। आम लोगों को केन्द्र में रखते हुए वैकल्पिक दीर्घकालीन पुनर्वास-विकास नीति, आपदा प्रबंधन और नागरिक निगरानी समिति गठित करने की भी जरूरत महसूस की गई।

उत्तराखण्ड के आपदा-प्रभावित लोगों से सलाह-मसविदा करके एसयूसीआई(सी) द्वारा 3 अगस्त को यहां के श्रीनगर शहर में एक नागरिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता उत्तराखण्ड के सुप्रसिद्ध प्रगतिशील कवि नरेन्द्र सिंह नेगी ने की। श्रीनगर नगरपालिका परिषद् के सभागार

में हुए इस सम्मेलन में वैज्ञानिक, दार्शनिक, इतिहासविद्, साहित्यकार एवं आपदा-पीड़ित लोग शामिल हुए। सम्मेलन में 16-17 जून को आई आपदा के कारण, आपदा प्रबंधन, राहत कार्य, दीर्घकालीन पुनर्वास-विकास, तत्कालीन राहत आदि विषयों पर चर्चा हेतु प्रो. आर.सी. डिमरी द्वारा पेश एक प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव में सरकार से आपदा-पीड़ित क्षेत्रों के सभी विद्यार्थियों की सारी फीस माफी, हरेक टूटे हुए रास्तों व पुलों का युद्ध स्तर पर पुनर्निर्माण, कम से कम एक साल के मुफ्त राशन की व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था को सस्ती बनाने के लिए परिवहन साधनों को सब्सिडाइज्ड रेट पर डीजल सल्लाई व टैक्स माफी की मांग की गई।

नरेन्द्र सिंह नेगी ने गहरी चिंता के साथ कहा कि हम आज हिमालय के मिजाज, नदियों के स्वभाव, पहाड़ों, जंगलों और भौगोलिक परिवर्तनों के कारण बिना जाने ही विकास की बात कर रहे हैं। इसलिए जो भी पर्यावरण के बारे में चिंता जताते हैं, उन्हें 'विकास-विरोधी' की संज्ञा दी जाती है। उन्होंने दीर्घकालीन पुनर्वास एवं विकास और फौरी राहत कार्यों में जनता की भूमिका को सराहना की। सम्मेलन की शुरुआत में ओ.पी. सेमवाल ने आह्वान गीत पेश किया। निर्मल चौधरी, प्रो. सुरेखा डंगवाल, एसयूसीआई(सी) के दिल्ली राज्य सचिव कॉ. प्रताप सामल, शिक्षक संघ के अध्यक्ष शिव सिंह नेगी, सचिव आनंद जगवान, प्रो. डी.आर. पुरोहित, डॉ. एस.पी. सती, घनश्याम पुरोहित, शिशुपाल पवार, प्रो. अतुल सकलानी आदि ने चर्चा में भाग लिया।

अंत में उत्तराखण्ड आपदा पुनर्वासन जन समिति गठित की गई। इसमें श्री नरेन्द्र सिंह नेगी को संरक्षक, प्रो. अतुल सकलानी, बी. मोहन नेगी, ओ.पी. सेमवाल, उत्तम सिंह चौधरी को संरक्षक मण्डल में लिया गया। इसके संयोजक मुकेश सेमवाल और सदस्य प्रो. आर.सी. डिमरी, डॉ. एस. पी. सती, डॉ. एस.एस. बिष्ट, सुरेश भट्ट, राजेन्द्र नैटियाल, शिशुपाल पवार, डॉ. पी.सी. चमौली, घनश्याम पुरोहित, सुदर्शन सेमवाल, निर्मल चौधरी, अवतार सिंह भण्डारी, राजेश बिष्ट व ब्रजमोहन सती को चुना गया।



सारण के मशरक में मिड डे मिल खाने से हुई 23 बच्चों की मौत की घटना ने उजागर कर दिया कि भ्रष्टाचार-कमीशनखोरी में लिप्त पूरे प्रशासनिक तंत्र और सर्वोपरि डपोरशंखी बिहार सरकार की लापरवाही इन मासूमों की मौत की जिम्मेवार है। शिक्षा-स्वास्थ्य भी बदहाल है। अधिकांश स्कूल भवन, शिक्षक, बेंच-डेस्क सहित बुनियादी सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच डाक्टरों, नर्सों व तकनीशियनों की कमी से जूझ रहा है। हैरत तो तब होती है जब इसके इमरजेंसी ऑपरेशन थियेटर में भी सीरिज, स्प्रिट और दवाओं का घोर अभाव पाया जाता है। आम जनता के पैसे से निर्मित राज्य परिवहन को निजी मालिकों के मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली-इन तमाम क्षेत्रों में पीपीपी के तहत निजीकरण को प्रक्रिया तेजी से लागू की जा रही है।

धरना की अध्यक्षता एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) राज्य कमिटी सदस्य कॉ. शिवलाल प्रसाद ने की जबकि संचालन पटना जिला कमिटी सदस्य कॉ. राजकुमार चौधरी ने किया। धरना को पार्टी के राज्य कमिटी के वरिष्ठ सदस्य कॉ. एम. के. पाठक, पटना जिला सचिव साधना मिश्रा, जिला कमिटी सदस्य अरुण कुमार, राजेन्द्र राय, सूर्यकर जितेन्द्र, अनामिका, अनिल कुमार चांद, सरोज कुमार सुमन ने संबोधित किया।